● वर्ष-5
● अंक-255
रायपुर, गुरुवार
11 जून 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› 47वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर सीएम ...

प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल : दुनिया ने किया सलाम

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रचते हुए देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने केंद्र सरकार में 12 साल पूरे कर लिए हैं। इस अहम कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीतिक ताकत में बदल गई है, लगातार नए इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ा रही है और कई समुदायों से बड़ा समर्थन हासिल कर रही है। बुधवार को प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिन पूरे करके, पीएम मोदी ऑफिशियली भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए।

मालूम हो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने असल में 1947 में पद संभाला था और 1951-52 में देश का पहला आम चुनाव जीता था, लेकिन वे 1964 में अपने निधन तक इस पद पर बने रहे। वहीं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 16 साल से थोड़ा कम समय तक सेवा की, लेकिन उनका कार्यकाल दो अलग-अलग समय में फैला हुआ था।

इस ऐतिहासिक कामयाबी को पहचानते हुए, दुनिया भर के जाने-माने ग्लोबल नेताओं ने पीएम मोदी को दिल से बधाई दी, और उनके बदलाव लाने वाले शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके जोशीले सपोर्ट और एक सबको साथ लेकर चलने वाले और आर्थिक रूप से डायनामिक भारत बनाने के उनके बड़े विजन को बड़े पैमाने पर माना।

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने देश की ग्लोबल तरक्की में भारतीय नेता के बहुत बड़े योगदान की तारीफ करते हुए इंटरनेशनल तारीफों का सिलसिला शुरू किया।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, इब्राहिम ने कहा, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर पीएम मोदी को दिल से बधाई। यह उपलब्धि भारत के विकास, समृद्धि और ग्लोबल स्टेज पर उसकी पहचान बनाने में उनकी सालों की समर्पित पब्लिक सर्विस और लीडरशिप का सबूत है। मलेशिया भारत के साथ अपनी करीबी और पुरानी दोस्ती को महत्व देता

है, और मैं द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हमारे लोगों के लिए मौके बढ़ाने में हमारे सहयोग को जारी रखने की उम्मीद करता हूं। मैं पीएम मोदी को लगातार सफलता और भारत के लोगों को लगातार शांति, तरक्की और समृद्धि की कामना करता हूं। डिप्लोमैटिक कम्युनिटी की इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए, भारत में यूनाइटेड स्टेट्स के राजदूत सर्जियो गोर ने भी एक्स पर प्रधानमंत्री के लंबे राजनीतिक सफर की तारीफ की। राजदूत गोर ने पोस्ट किया, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। यह उपलब्धि उनकी दशकों की समर्पित पब्लिक सर्विस और लीडरशिप का एक मजबूत सबूत है! उन्हें शुभकामनाएं! इंटरनेशनल बधाइयों की लहर ने भारत की अपने आस-पास के इलाकों में गहरी पार्टनरशिप को और हाईलाइट किया। नई दिल्ली और कोलंबो के बीच करीबी रिश्तों को दोहराते हुए, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका ने एक खास बातचीत में पीएम मोदी के लंबे समय तक चलने वाले डेमोक्रेटिक जनादेश की बहुत तारीफ की।बधाई संदेश में राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा, यह उपलब्धि न केवल आपके कार्यकाल के वर्षों का प्रमाण है, बल्कि उस भरोसे और विश्वास का भी सबूत है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता ने बार-बार आपके नेतृत्व पर जताया है।

भारत में श्रीलंका के उच्चायोग द्वारा एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार, राष्ट्रपति @anuradisanayake ने प्रधानमंत्री @narendramodi को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी है। यह संदेश श्रीलंका और भारत के बीच घनिष्ठ और स्थायी साझेदारी को और मजबूत करने के श्रीलंका के संकल्प को दोहराता है।

हिंद महासागर क्षेत्र से मिली प्रतिक्रियाओं में, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल के दौरान क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में उनकी रचनात्मक भूमिका की अत्यधिक सराहना की।

एक्स पर एक पोस्ट में नशीद ने कहा, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। इस लंबे कार्यकाल के दौरान, हमने न केवल प्रधानमंत्री को भारत के लोगों की सेवा करते देखा है, बल्कि मालदीव और इस क्षेत्र को भारत की सहायता भी देखी है, जिससे हमारे लोगों की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में मदद मिली है। @narendramodi"

भारत के मजबूत रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करते हुए, भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने एक्स पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच समानता बताते हुए दोनों नेताओं की परिवर्तनकारी शासन शैली की सराहना की। इजराइली राजनयिक ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों ने देश की वित्तीय दिशा को सफलतापूर्वक बदल दिया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में राजदूत अजार ने कहा, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर श्री @narendramodi को बधाई! दोनों करीबी सहयोगी देशों के बीच रणनीतिक दृष्टिकोण और नेतृत्व की समानता की सराहना करते हुए, राजदूत ने आगे कहा, आपके मित्र और इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री @netanyahu की तरह, आपने कई गहरे सुधारों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया है।

एनडीए सम्मेलन में भाग लेने वाली पार्टियाँ

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके), शिव सेना (एसएचएस), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), लोक जनशक्ति पार्टी-राम विलास (एलजेपी-आरवी), नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी), ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (एजेएसयू), अपना दल सोनीलाल (एडीएस), असम गण परिषद (एजीपी), जन सेना पार्टी (जेएसपी), जनता दल सेक्युलर (जेडीएस), नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ), सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम), टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी), बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ), पट्टाली मक्कल काची (पीएमके), भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (एचएएम), निषाद पार्टी।

विकसित भारत की स्वर्णिम यात्राः विष्णु देव साय

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा के 12 वर्ष पूरे होना उस परिवर्तनकारी कालखंड का प्रतीक है, जिसने देश की दशा और दिशा को बदला है। वर्ष 2014 में देश ने एक ऐसे नेतृत्व पर विश्वास जताया, जिसने शासन को सत्ता का माध्यम नहीं, सेवा का संकल्प माना। इन 12 वर्षों में भारत ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है।

प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को केवल नारा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे शासन की कार्यसंस्कृति बनाया। गरीब कल्याण इस दौर की सबसे बड़ी पहचान रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को पक्का घर दिया। आयुष्मान भारत ने गरीब परिवारों को महंगे इलाज की चिंता से राहत दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने अन्नदाताओं को सीधी आर्थिक सहायता दी। ये योजनाएं केवल सरकारी घोषणाएं नहीं रहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा व विश्वास का आधार बनीं।

इन 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने भी नई शक्ति प्राप्त की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश को केवल उपभोक्ता बाजार नहीं रहने दिया, बल्कि उत्पादन, नवाचार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत केंद्र बनाने की दिशा दी। मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रानिक्स, रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर, फार्मा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। डिजिटल इंडिया ने भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। यूपीआइ ने डिजिटल भुगतान को आम आदमी के जीवन का हिस्सा बना दिया है। गांवों तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच ने शासन को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया है।आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी पिछले 12 वर्ष ऐतिहासिक रहे हैं। आधुनिक राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस-वे, वंदे भारत ट्रेनें, नए एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, अमृत भारत स्टेशन और बेहतर लाजिस्टिक्स ने देश की गति बढ़ाई है। सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी ने उन क्षेत्रों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है, जो लंबे समय तक उपेक्षित रहे थे। छत्तीसगढ़ में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में हमें मोदी की गारंटी पर जनादेश मिला। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह देकर महिला सशक्तीकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है।आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई इस कालखंड की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। वर्षों तक देश के अनेक आदिवासी और वनांचल क्षेत्र नक्सली हिंसा, भय और पिछड़ेपन के चक्र में फंसे रहे।

प्रमुख समाचार

राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को पीएम नरेन्द्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने की विशिष्ट उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर उनके नेतृत्व में जनता द्वारा जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण

है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, आपका कार्यकाल शासन, आर्थिक मजबूती और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी उपलब्धियों से चिह्नित रहा है।'' मोदी देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के लगातार कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।''राष्ट्र के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने के इस अद्वितीय सम्मान पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक बधाई। यह ऐतिहासिक अवसर भारत की जनता द्वारा आपके नेतृत्व में व्यक्त किए गए स्थायी विश्वास और भरोसे का प्रमाण है।''

पीएम मोदी ने बिना छुट्टी लिए देश की सेवा की : रेखा गुप्ता

नईदिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेन्द्र मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर बुधवार को उत्तरी दिल्ली की किशनगंज गौशाला का दौरा किया और एक मंदिर में पूजा-अर्चना की। गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा कि आज वह

(मोदी) सबसे लंबे समय तक पद रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं और वह बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए, देश की सेवा कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि करोड़ों लोग प्रधानमंत्री के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर कोई देश का सम्मान बढ़ाने और विकसित भारत के उनके दृष्टिकोण के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता है, जिसके लिए वह निरंतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं के केंद्र में महिलाएं हैं, चाहे वह देशभर में शौचालयों को बढ़ावा देकर उन्हें सम्मान देना हो या उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराकर उनके जीवन को आसान बनाना हो।

नटराजन मामले में चुनाव आयोग से मिले कांग्रेस नेता

भोपाल। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द किए जाने के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बुधवार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग से

मुलाकात कर रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को गलत, पक्षपातपूर्ण और कानून के विरुद्ध बताते हुए उसे तत्काल निरस्त करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जयराम रमेश, दीपा दासमुंशी, विवेक तन्खा, अभिषेक मनु सिंघवी और स्वयं मीनाक्षी नटराजन शामिल थीं। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के समक्ष तर्क रखा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।उनके खिलाफ दायर निजी शिकायत पर अभी तक किसी अदालत ने संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे में कानून की नजर में उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण अस्तित्व में ही नहीं माना जा सकता था।

टीएमसी की सुष्मिता देव ने सांसद पद से दिया इस्तीफा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर मची अंदरूनी कलह और बगावत अब दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी पर पकड़ लगातार कमजोर होती दिख रही

है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बागी नेता रिताब्रता बनर्जी के समर्थन में 61 विधायकों के लामबंद होने के बाद, अब यह असंतोष संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) में भी फूट पड़ा है। पार्टी के बेहद भरोसेमंद और वरिष्ठ सहयोगी सुखेंदु शेखर रॉय के राज्यसभा से इस्तीफा देने के ठीक एक हफ्ते बाद, बुधवार को टीएमसी की तेजतर्रार नेता सुष्मिता देव ने भी उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक ही हफ्ते के भीतर दो बड़े राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे ने ममता बनर्जी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। सुष्मिता देव देश की राजनीति, विशेषकर उत्तर-पूर्व का एक जाना-माना चेहरा हैं।

राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच हुई अहम बैठक

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। यह बैठक 10 जनपथ पर हुई। विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच तालमेल बढ़ाने और एकता बनाए रखने की कोशिशों के तहत यह मुलाकात काफी अहम मानी जा

रही है। यह बैठक ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात के ठीक एक दिन बाद हुई है। मंगलवार को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी के आवास पर जाकर उनसे बात की थी। उस दौरान दोनों नेताओं ने विपक्षी गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करने के रास्तों पर चर्चा की थी। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की यह मुलाकात इस हफ्ते दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक का ही हिस्सा है। उस बैठक में विपक्षी दलों ने भाजपा का मुकाबला करने के लिए आपसी सहयोग और एकता की जरूरत बताई थी। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं ने बगावती तेवर दिखाए हैं। सोमवार को हुई गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने सभी साथियों से अपील की थी कि वे अपने मतभेद किनारे रख दें।

मोदी बने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री

नीरज कुमार दुबे

मोदी हैं तो मुमकिन है, यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि पिछले बारह वर्षों में भारत की बदलती राजनीतिक और प्रशासनिक तस्वीर का सबसे सशक्त प्रतीक बन चुका है। जिस उपलब्धि को दशकों तक असंभव माना जाता रहा, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभव कर दिखाया है। 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। लगातार 4399 दिनों तक देश का नेतृत्व करते हुए उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु के 4398 दिनों के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

यह उपलब्धि केवल एक रिकॉर्ड टूटने भर की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में आए एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक भी है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ नेहरू का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है बल्कि उस राजनीतिक सोच को भी चुनौती दी है जिसमें लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि सत्ता पर केवल एक ही परिवार या एक ही दल का स्वाभाविक अधिकार है। दशकों तक देश की राजनीति गांधी परिवार और कांग्रेस पर केंद्रित रही, लेकिन एक गरीब परिवार से निकले, संघर्षों के बीच पले-बढ़े और कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की ताकत के बल पर देश की सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचकर भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी।

मोदी का यह सफर करोड़ों सामान्य भारतीयों के लिए प्रेरणा का विषय है। यह संदेश देता है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, और जनता जब ठान ले तो वह किसी भी स्थापित राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है। लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए और सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाकर नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया है कि मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट विजन और जनता के भरोसे के दम पर भारतीय राजनीति में असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।

मोदी ने जो रिकॉर्ड बनाया है वह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह उस जनविश्वास की कहानी है जिसने नरेंद्र मोदी को लगातार तीन बार देश की

सत्ता सौंपी। आजादी के बाद केवल जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे नेता थे जिन्होंने लगातार तीन लोकसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी। नरेंद्र मोदी ने भी वही करिश्मा दोहराया, लेकिन उससे आगे जाकर लोकतांत्रिक राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले वर्षों में वह भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली और निर्णायक नेता बनकर उभरेंगे। 2019 में उन्होंने पहले से भी अधिक प्रचंड जनादेश हासिल किया और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2024 के चुनाव में भले भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े से नीचे रही, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की चमक और प्रभाव जरा भी कम नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने फिर सत्ता संभाली और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।

दरअसल नरेंद्र मोदी का यह सफर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक प्रशासन संभालते हुए सुशासन का एक अलग मॉडल प्रस्तुत किया। अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 4610 दिनों तक राज्य की कमान संभाली। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मिलाकर मोदी अब नौ हजार दिनों से अधिक समय तक किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख रह चुके हैं। मार्च 2026 में उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का 8930 दिनों का रिकार्ड भी तोड़ दिया था और देश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले निर्वाचित प्रमुख बन गए थे।

उधर, मोदी के इस ऐतिहासिक मुकाम पर केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से उन्हें बधाइयों का सिलसिला मिला। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं देते हुए भारत और इटली के मजबूत होते रिश्तों का उल्लेख किया। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने इसे दशकों की समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का प्रमाण बताया। अमेरिकी सीनेटर जॉन कोर्निन ने मोदी के कार्यकाल को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि 140 करोड़ लोगों के विश्वास ने उन्हें यह मुकाम दिलाया है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले।

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी मोदी की उपलब्धि को भारत की समृद्धि, विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा से जोड़ा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को समर्पण, संघर्ष और जनसेवा का प्रतीक बताया। यह साफ संकेत है कि आज नरेंद्र मोदी केवल भारत के नेता नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन चुके हैं।

उधर, देश के भीतर भी मोदी की इस उपलब्धि को लेकर उत्साह का माहौल है। भाजपा नेताओं ने आज देशभर के विभिन्न धर्म स्थलों में प्रार्थना कर भारत की खुशहाली और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने की कामना की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा की।इसके अलावा, दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की गयी और एक अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। यह बैठक सत्तारुढ़ एनडीए की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की।

बहरहाल, नरेंद्र मोदी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि उन्होंने खुद को केवल एक नेता नहीं, बल्कि बदलाव के प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला यह सफर आज करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा बन चुका है। यही कारण है कि जब देश की राजनीति में असंभव को संभव करने की बात होती है, तब एक ही आवाज सबसे ज्यादा गूंजती है— मोदी हैं तो मुमकिन है

माड़ संवाद: आधी रात अबूझमाड़ के गांव पहुंचा प्रशासन

जिस घोटूल में कभी बंदूक और भय का साया था, वहां आज विकास, शिक्षा और बेहतर भविष्य की चर्चा हो रही है.

कभी जनअदालत का गवाह रहा घोटूल बना विकास संवाद का मंच

नारायणपुर। अबूझमाड़ के दूरस्थ और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक शासन को पहुंचाने की दिशा में एक नई और अनोखी पहल शुरू की गई है। माड़ संवाद कार्यक्रम के माध्यम से कलेक्टर और जिले के वरिष्ठ अधिकारी अब गांवों में रात्रि चौपाल लगाकर सीधे ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार देर रात कलेक्टर नम्रता जैन और जिला प्रशासन की पूरी टीम जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित मसपुर गांव पहुंची, जहां आधी रात तक ग्रामीणों के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। यह वही मसपुर है, जो कभी नक्सलियों का सुरक्षित इलाका माना जाता था और जहां प्रशासन की पहुंच लगभग असंभव समझी जाती थी। मंगलवार रात करीब 8 बजे जब प्रशासनिक अमला मसपुर पहुंचा तो गांव के घोटूल प्रांगण में चौपाल सजाई गई। जिस घोटूल में कभी नक्सली जनअदालत लगाकर ग्रामीणों के जीवन और मौत के फैसले सुनाया करते थे, वहीं आज विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा हो रही थी। यह दृश्य अपने आप में अबूझमाड़ में आए परिवर्तन की एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करता है।

चौपाल के दौरान ग्रामीणों को बड़े एलईडी स्क्रीन पर फिल्म टॉयलेट- एक प्रेम कथा दिखाई गई। इसके साथ ही नारायणपुर और बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं से जुड़े वीडियो भी दिखाए गए। ग्रामीणों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने गांव की विभिन्न समस्याएं रखीं। इनमें सड़क निर्माण, स्कूल परिसर की बाउंड्रीवॉल, नवीन स्कूल भवन निर्माण, डबरी निर्माण, पेयजल व्यवस्था और ग्रामीण किशोरियों के लिए सेनेटरी पैड की नि:शुल्क उपलब्धता जैसी मांगें प्रमुख रहीं। कलेक्टर मैडम और बहुत सारे अधिकारी हमारे गांव में आए हैं। हम बताया जा रहा है कि घर में शौचालय का होना कितना जरूरी है। हमसे वादा किया गया है कि जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो हमें यहां मिलेगी- शामी पोटाई, ग्रामीण महिला कार्यक्रम में शामिल ग्रामीणों ने बताया कि आज से एक वर्ष पहले तक नक्सली संगठन के दबाव के कारण उन्हें स्वतंत्र रूप से कहीं आने-जाने की अनुमति नहीं थी। गांवों में भय का माहौल बना रहता था और शासन-प्रशासन से उनका सीधा संपर्क लगभग नहीं के बराबर था। लेकिन नक्सलवाद के कमजोर पड़ने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बाद हालात तेजी से बदले हैं। अब सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी सीधे गांवों तक पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद की समाप्ति के घोषित लक्ष्य के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है। जिन क्षेत्रों में कभी विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहां अब सड़क, बिजली, पानी, राशन, स्वास्थ्य सेवाएं और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का लाभ दिखाई देने लगा है। माड़ संवाद कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब देखने को मिला जब संवाद समाप्त होने के बाद कलेक्टर और अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया।

हुर्रगुवाली पंचायत पहुंचा प्रशासनिक अमला

बीजापुर में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पीएमजीएसवाय के तहत चल रहे योजनाओं की समीक्षा की.

बीजापुर। कभी बम धमाकों और गोलियों की गूंज से जाना जाने वाला भैरमगढ़ अब विकास के कामों से पहचाना जाने लगा है। माओवादियों के डर से जिन गांवों में अफसर कभी जाने से कतराते थे, आज उन गांवों में प्रशासनिक अमला पहुंचकर किसानों के साथ बैठक कर रहा है। मंगलवार को बीजापुर का प्रशासनिक अमला नदी पार कर भैरमगढ़ के नुगुर गांव के हुर्रगुवाली पंचायत पहुंचा। इस प्रशासनिक अमले में कलेक्टर विश्वदीप और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे शामिल थीं। गांव वालों के साथ चौपाल में बैठक कर अफसरों ने गांव और उनके इलाके के विकास कार्यों पर चर्चा की। अफसरों को अपने बीच पाकर गांव वालों ने भी सड़क, आवास, धान खरीदी, शिक्षा, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि गांव में शासन की योजनाओं को पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है- विश्वदीप, कलेक्टर, बीजापुर कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि क्षेत्र में आवागमन सुगम हो सके और विकास को गति मिल सके। बैठक में ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केतूलनार में धान खरीदी केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। साथ ही नदी के इस पार से धान उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर अधिकारियों ने ग्रामीणों को ठोस आश्वासन दिया। कलेक्टर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि धान बेचने के लिए बिचौलिए से संपर्क मत करें। धान खरीदी केंद्र पर जाएं सीधे अपना धान तय समर्थन मूल्य पर बेचें। अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि शासन द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी एवं 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है।

शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप

अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारियों से विवाद

कबीरधाम। खपरी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान पंचायत एवं माध्यमिक शाला परिसर के पास स्थित शासकीय भूमि और माता देवालय के पास की गौचर भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण की शिकायत प्रशासन से की गई थी। शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग की टीम और पटवारी मौके पर जांच के लिए पहुंचे थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया गया है कि जांच और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों ने प्रशासनिक कार्य में बाधा पहुंचाई तथा शिकायतकर्ताओं को डराने-धमकाने का प्रयास किया। ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग करने पर उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि एक ग्रामीण पर सामूहिक हमला किया गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति के हाथ में दांत से काटकर चोट पहुंचाई गई। सुशासन तिहार में अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दिया था। जब अनावेदकों को बुलाया गया तो उन्होंने हमला कर दिया। बीचबचाव करने आए लोगों पर हमला किया गया। पिपरिया थाना में शिकायत करने पहुंचे थे ग्रामीण।

धमतरी के जंगलों में दिखा हिरणों का खूबसूरत झुण्ड

कलेक्टर ने कैमरे में कैद किया नजारा

धमतरी। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला अपनी खूबसूरत प्रकृति और जंगली जानवरों के लिए लगातार मशहूर हो रहा है। यहां के घने जंगलों में हिरण, तेंदुए, भालू और कई तरह के अनोखे जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। हाल ही में, धमतरी के कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अपनी सरकारी यात्रा के दौरान हिरणों के झुंड को मोबाइल में कैद किया।

कुछ दिन पहले कलेक्टर अबिनाश मिश्रा एक इलाके का दौरा करके लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें हिरणों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। खुले आसमान और शांत जंगल के बीच हिरणों को घूमते देख कलेक्टर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से इसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया और जिले की इस प्राकृतिक सुंदरता पर खुशी जताई।

कलेक्टर ने बताया कि जो लोग प्रकृति और जानवरों से प्यार करते हैं, उनके लिए धमतरी एक बेहतरीन जगह है। यहाँ का दुगली फॉरेस्ट रेंज और उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व जानवरों के रहने के लिए सबसे अच्छे इलाके हैं। यहाँ उड़ने वाली गिलहरी (फ्लाइंग स्क्विरल) से लेकर तेंदुए जैसे दुर्लभ जीव भी मिलते हैं।

यहां के जंगलों में तेंदुए अच्छी-खासी संख्या में हैं। इसके अलावा, यहां कई तरह के रंग-बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जिससे यह जगह बर्ड वॉचिंग (पक्षी देखने) के लिए भी बहुत मशहूर हो रही है।कलेक्टर ने कहा कि अगर आप शहरों की भागदौड़ से दूर और प्रकृति के करीब होना चाहते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो एक बार धमतरी जरूर घूमने आएं। यहां के शांत जंगल, ठंडी हवा और वन्यजीव आपको एक बिल्कुल अलग और सुकून देने वाला अनुभव देंगे।

खूबसूरत नजारा एक बार फिर दिखाता है कि धमतरी जिला जंगलों और जानवरों को सुरक्षित रखने के मामले में छत्तीसगढ़ का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बस्तर में तेंदूपत्ता खरीदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, लेकिन 50 हजार संग्राहकों ने बनाई दूरी

जगदलपुर। बस्तर संभाग में इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्रहण को लेकर रिकॉर्ड आंकड़े सामने आए हैं। वन विभाग ने दावा किया है कि जगदलपुर सर्किल के चार जिलों में 1 लाख 74 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता खरीदा गया है, जिससे करीब 96 करोड़ रुपये की राशि संग्राहकों तक पहुंची है। हालांकि इन दावों के बीच कई ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं, जो तेंदूपत्ता कारोबार की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार क्षेत्र में लगभग 1 लाख 75 हजार संग्राहक पंजीकृत हैं, लेकिन तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में केवल 1 लाख 25 हजार लोग ही शामिल हुए। यानी करीब 50 हजार पंजीकृत संग्राहकों ने इस बार तेंदूपत्ता तोड़ने का काम नहीं किया। इतनी बड़ी संख्या में संग्राहकों के प्रक्रिया से बाहर रहने के पीछे के कारणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर मजदूरी, मौसम और संग्रहण से जुड़ी अन्य चुनौतियों को इसकी एक वजह माना जा रहा है। वन विभाग ने भी माना है कि बेमौसम बारिश का असर संग्रहण पर पड़ा। बारिश के कारण 60 से 70 गांवों में तेंदूपत्ता संग्रहण प्रभावित हुआ। अधिकारियों का कहना है कि यदि मौसम अनुकूल रहता तो खरीदी और संग्रहण का आंकड़ा इससे भी अधिक हो सकता था। इसके अलावा 1702 फड़ों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 1600 फड़ों में ही संग्रहण कार्य हो पाया।

गांजा तस्कर निकला नगर सैनिक, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

धमतरी। मादक पदार्थों की तस्करी का लंबे वक्त से गढ़ रहा है धमतरी जिला। बड़ी मात्रा में गांजे की तस्करी ओडिशा के बार्डर एरिया से यहां होती है। आए दिन यहां पुलिस की नाकेबंदी और छामेमारी में गांजा तस्कर पकड़े जाते हैं, बावजूद इसके नशे का कारोबार घटने के बजाए बढ़ता ही जा रहा है। इस साल अप्रैल के महीने में गांजा बिक्री के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक नगर सैनिक पकड़ा गया था। जांच के दौरान से सिद्ध हुआ कि नगर सैनिक गांजे की तस्करी में लिप्त रहा है। उसकी संलिप्तता जाहिर होने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मगरलोड पुलिस के मुताबिक 14 अप्रैल 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) और 29 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

इस प्रकरण में पहले ही 1 l660 किलोग्राम अवैध गांजा, नगद राशि और मोबाइल फोन सहित कुल 89 हजार 930 रुपये की सामग्री जब्त कर पति-पत्नी आरोपी लाभाराम कुर्रे और सुशीला बाई कुर्रे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस द्वारा मामले की गहन विवेचना, तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। इस दौरान मामले में एक और आरोपी की भूमिका सामने आई। जांच में पता चला कि ग्राम पाहन्दा निवासी महेश सिन्हा, जो नगर सैनिक के रूप में कार्यरत है, अवैध गांजा कारोबार से जुड़ा हुआ था और उसकी इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका रही है। पुलिस ने आरोपी की लगातार निगरानी की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

डबल ब्लाइंड मर्डर मामले में दो आरोपी समेत व्यापारी जेल

सक्ती। जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के सेंदुरस गांव में पति-पत्नी हत्याकांड और लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में दो आरोपियों समेत लूट का माल खरीदने वाले एक सराफा व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है।जांच में यह भी सामने आया है कि यही दोनों आरोपी वर्ष 2024 में मुक्ता गांव में हुए चर्चित डबल मर्डर केस में भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार, 2 और 3 जून 2026 की दरमियानी रात सेंदुरस गांव में घर के बरामदे में सो रहे पुरुषोत्तम खुंटे और उनकी पत्नी गुहारिन बाई खुंटे की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद सोने के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन भी गायब मिले थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, एएसपी पंकज पटेल, एसडीओपी भुवनेश्वरी पैंकरा, साइबर सेल, डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम को जांच में लगाया गया। मोबाइल टावर डंप, कॉल डिटेल और सीईआईआर पोर्टल की मदद से पुलिस आरोपी देवकुमार यादव तक पहुंची, जिसके पास से मृतक का मोबाइल बरामद हुआ।

जहरीले धुएं से लोग परेशान कांग्रेस पार्षदों ने किया प्रदर्शन

धमतरी। जिले में ट्रेचिंग ग्राउंड में 20 दिनों से लगी आग से फैल रहा धुआं आस-पास के वार्डों के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। धुएं से परेशान वार्डवासियों के साथ कांग्रेस पार्षदों ने सोरिद वार्ड स्थित ट्रैंचिंग ग्राउंड के बाहर प्रदर्शन कर नगर निगम के लापरवाही के खिलाफ आक्रोश जताया। कांग्रेस पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिनों के भीतर आग पर काबू नहीं पाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दरअसल, धमतरी के सोरिद वार्ड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगी आग पिछले करीब 20 दिनों से लगातार सुलग रही है। आग की वजह से उठ रहा जहरीला धुआं आस-पास के रिहायशी इलाकों तक फैल गया है, जिससे लोगों का घरों में रहना तक मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चे और बुजुर्ग सहित कई लोग बीमार पड़ रहे हैं।कांग्रेस नेताओं का कहना है कि निगम ने ही कचरे में आग लगाई है, जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

जमातपारा में पुलिस ने दो लोगों पर की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

राजनांदगांव। शहर के जमातपारा क्षेत्र में मंगलवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब एक प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय में कथित रूप से संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने वहां मौजूद एक युवती को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। मंगलवार को लोगों ने एक युवती और एक व्यक्ति को कार्यालय के भीतर देखकर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती और कैलाश लॉज संचालक प्रीमन कुमार जैन उर्फ अप्पू जैन को अपने संरक्षण में लेकर थाने पहुंचाया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की, लेकिन अधिकारियों के अनुसार पूछताछ के दौरान संतोषजनक जानकारी नहीं मिल सकी। बसंतपुर थाना पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।

10 लाख की हेरोइन के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

दुर्ग। जिले में ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक आर्किटेक्ट को फर्जी ई-चालान लिंक भेजकर साइबर अपराधियों ने उसके क्रेडिट कार्ड से 4 l24 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन खरीदारी कर दी। शिकायत मिलने के बाद स्मृति नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि राजनांदगांव निवासी 30 वर्षीय अंकेश सिन्हा अपने ससुराल शिक्षक नगर, कोहका आए हुए थे। इसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर एम-परिवहन के नाम से एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उनके एक्टिवा वाहन पर 1000 रुपए का ई-चालान कटने की जानकारी दी गई थी।संदेश में एक लिंक भी दिया गया था, जिस पर क्लिक कर चालान भुगतान करने का निर्देश था।अंकेश ने संदेश को सही मानते हुए लिंक पर क्लिक कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद उनके क्रेडिट कार्ड से दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन किए गए। पहले ट्रांजेक्शन में 1 l31 लाख रुपए और दूसरे में 2 l92 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई।

हाथी ने फार्म हाउस और खेतों को पहुंचाया भारी नुकसान

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मरवाही वन मंडल क्षेत्र में चार हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है। बीती रात हाथियों का समूह जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया तो सुबह के समय एक फार्म हाउस सहित आस-पास के खेतों में जमकर नुकसान पहुंचाया। हाथियों की मौजूदगी से क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी कर रही है और प्रभावित लोगों को नुकसान का मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार देर रात चार हाथियों का दल मरवाही के नर्सरी के आस-पास ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया। इसके बाद यह हाथियों ने मरवाही निवासी दीपक जायसवाल के फार्म हाउस में प्रवेश कर भारी नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने सबसे पहले फार्म हाउस की बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया और परिसर के भीतर घुस गए। इसके बाद उन्होंने वहां रखे आम को तहस-नहस कर दिया। हाथियों के उत्पात से फार्म हाउस को काफी नुकसान पहुंचा है।

बस्तर के 382 केंद्रों में अब भी 40 हजार टन धान का उठाव बाकी

मानसून में नुकसान का खतरा

जगदलपुर। सरकारी रिकॉर्ड में धान खरीदी का सीजन भले समाप्त हो चुका हो, लेकिन बस्तर संभाग के सैकड़ों धान खरीदी केंद्रों में अब भी हजारों मैट्रिक टन धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। खरीदी प्रक्रिया खत्म होने के करीब चार महीने बाद भी धान का पूरा उठाव नहीं हो पाया है। ऐसे में मानसून की शुरुआत के साथ ही धान की सुरक्षा और सरकारी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं।संभाग के विभिन्न जिलों में किसानों से खरीदा गया धान अभी तक पूरी तरह गोदामों तक नहीं पहुंच सका है। बारिश शुरू होने के बाद कई केंद्रों से धान भीगने और खराब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं खुले में रखे धान को चूहों और अन्य कारणों से नुकसान पहुंचने की आशंका भी बढ़ गई है। केंद्र प्रबंधकों का कहना है कि समय पर उठाव नहीं होने से उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस्तर जिले के 79 धान खरीदी केंद्रों में इस सीजन 2 लाख 81 हजार 742 मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई थी। हालांकि खरीदी समाप्त होने के महीनों बाद भी 7 हजार 750 मैट्रिक टन से ज्यादा धान केंद्रों में ही पड़ा हुआ है। यह स्थिति तब है जब परिवहन और भंडारण की प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। समस्या केवल बस्तर जिले तक सीमित नहीं है। दंतेवाड़ा को छोड़कर बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों में खरीदी केंद्रों पर धान का लंबित उठाव चिंता का विषय बना हुआ है। गोदामों तक परिवहन की धीमी रफ्तार के कारण कई केंद्रों में जगह की कमी भी महसूस की जा रही है, जिससे आगामी सीजन की तैयारियों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। आंकड़ों के अनुसार बस्तर संभाग के 382 धान खरीदी केंद्रों में इस वर्ष कुल 13 लाख 74 हजार 383 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी।

अम्बिकापुर में सड़क किनारे ठेलों से जाम की दिक्कत

अंबिकापुर शहर में ठेला व्यवसायियों के कारण जाम की स्थिति बन रही है.जिससे आम जनता और निगम दोनों ही परेशान हैं.

सरगुजा। अंबिकापुर की आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से शहर में ठेले और गुमटियों की संख्या भी बढ़ी है। व्यवस्थित कार्ययोजना नहीं होने का परिणाम ये है कि इस समस्या से आम जनता, ठेले वाले और जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं। आम जनता परेशान है सड़क पर लगने वाले जाम से, क्योंकि सड़क किनारे ठेले लगने से सड़क पर जाम लगता है, दूसरी तरफ ठेले वाले परेशान हैं निगम की कार्रवाई से। निगम की मेयर ठेले वालों की मनमानी से परेशान हैं। अब इस समस्या का कोई बड़ा समाधान ही करना होगा। सिर्फ कार्रवाई करने से समस्या हल नही होगी।

पता चला की शहर में चौपाटी, आकशवाणी चौक, जैसे स्थानों में शाम होते ही जाम की स्थिति बन जाती है और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सड़क के दोनों किनारों पर ठेले लगते हैं। उसके सामने ग्राहक गाड़ियां खड़ी कर देते हैं।इसके बाद बीच में बची 4 से 5 फिट की जगह में ही ट्रैफिक का संचालन होता है। वहीं ठेले वालों का अपना रोना है उनका कहना है कि 25 साल से वो ठेला लगा रहे हैं और अब नगर निगम उन पर कार्रवाई करके सामान जब्त कर ले रहा है। इधर नगर निगम की मेयर मंजूषा भगत भी इस समस्या से परेशान हैं उनका कहना है कि दिन भर में 80 प्रतिशत फोन सिर्फ इसलिए लोग करते हैं कि वो जाम से परेशान हैं। वो लोग कहते हैं कि आप शहर को डूबा देंगी, मैं कई बार ठेले वालों के पास गई उनको समझाने लेकिन वो मानते नहीं है। बहरहाल, समस्या फिलहाल बने रहेगी क्योंकि कंपनी बाजार में सड़क का बाजार शिफ्ट किया जाएगा।

लेकिन इसके निर्माण में कम से कम एक वर्ष का समय लगेगा तब तक स्थिति ऐसी ही रहने वाली है।जनप्रतिनिधि के लिए आम जनता हो या ठेले वाले सभी उनके नागरिक हैं।

संक्षिप्त समाचार

विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दें : राज्यपाल डेका

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से बुधवार

को लोक भवन में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति तथा वहां उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर देते हुए संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने तथा उनके लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों की शिक्षा, छात्रावास सुविधा, विद्यालयीन अधोसंरचना और शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़े विषयों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाना चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्राप्त हो सकें और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

वन विभाग में चार वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वरिष्ठ स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। जारी आदेश के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं मूल्यांकन) कोलेन्द्र कुमार को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वन विभाग में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के तहत ओपी यादव को प्रभारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) तथा सह-मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के पद पर पदस्थ किया गया है। वर्ष 2001 बैच की वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी शालिनी रैना को मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे वर्तमान में वन मुख्यालय में प्रशासन, समन्वय तथा राजपत्रित-अराजपत्रित कार्मिकों से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। इसके अलावा माधेश्वर डी. को प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास एवं योजना, बजट, लेखा एवं लेखा परीक्षण) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे वर्तमान में वन्यजीव प्रबंधन एवं योजना, राज्य जैव विविधता बोर्ड तथा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण से जुड़े विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं।

मंत्री राजवाड़े की पहल से लटोरी तहसील में स्थापित हुआ वाटर फिल्टर

रायपुर। प्रदेश में नागरिकों को बेहतर मूलभूत

सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से सूरजपुर जिले के लटोरी तहसील परिसर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वाटर फिल्टर स्थापित किया गया है। इस पहल से तहसील कार्यालय आने वाले ग्रामीणों, किसानों तथा आमजनों को गर्मी के मौसम में स्वच्छ एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने क्षेत्रवासियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तहसील परिसर में पेयजल सुविधा सुदृढ़ करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत स्थापित किए गए वाटर फिल्टर से प्रतिदिन बड़ी संख्या में तहसील पहुंचने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इससे न केवल पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि आमजन को स्वच्छ जल प्राप्त होने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी मिलेंगे। इस अवसर पर तहसीलदार श्री सुरेंद्र पैकरा ने मंत्री श्रीमती राजवाड़े के जनहितैषी प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि तहसील परिसर में वाटर फिल्टर की स्थापना से आने वाले सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधि संगठनों के पदाधिकारियों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

47वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर सीएम साय ने दी विस अध्यक्ष सिंह को शुभकामनाएं

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं श्रीमती वीणा सिंह को 47वीं वैवाहिक वर्षगांठ की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप दोनों सदैव स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रहें तथा प्रभु आपको दीर्घायु, आरोग्य और आनंदमय दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें।

पीएम मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण, मंदिरों में की गई विशेष पूजा

रायपुर। नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही है। लोग हवन पूजन करके इस दिन को मना रहे हैं। बात रायपुर की करें तो राजधानी के आकाशवाणी चौक पर स्थित काली माता मंदिर में सुबह मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पूरा होने पर हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई। इस हवन पूजन के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी, रायपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता, अनुषांगिक संगठन सभी मिलकर के प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को इसी तरह से देश की सेवा करते रहने का, देश के लिए मान सम्मान स्वाभिमान के लिए देश की सुरक्षा के लिए गरीबों के कल्याण के लिए उनके कार्यकाल को याद किया जाएगा।

रामविचार नेताम ने कहा आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का शपथ लिया था।

इसलिए हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे नेता सभी मिलकर के आज भगवान के दरबार में आकर के उनके लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना की जा रही है। वहीं इस मौके पर रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 12 साल पूरे होने पर हवन का आयोजन किया गया था। इन 12 सालों में देश में जो परिवर्तन आया है। एक विकसित भारत की ओर देश बढ़ रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, नया भारत और विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आया है।

विधायक सुनील सोनी ने कहा 212 योजनाओं की मदद से आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाए हैं। खासकर महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। उनको एक घर मिला, एक बिजली का कनेक्शन मिला, नल की टोटी मिली और एक गैस का सिलेंडर मिला। उनको लगा कि जीवन का सारा सपना पूरा हो गया।

सुनील सोनी ने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल पूरे होने पर आज हम काली माता के मंदिर में पूजा अर्चना और हवन किए हैं। मोदी जी दीर्घायु हो। इसी प्रकार से देश की सेवा करते रहें। इस बात का हम सबको गर्व है कि आज हमारे प्रधानमंत्री विश्व के सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। भारत के नाम को आगे बढ़ाया है।

मंत्री राजवाड़े ने की विशेष प्रार्थना

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने तथा देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर को भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए युग का प्रतीक बताया। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े रायपुर स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्रसेवा के उनके संकल्प की निरंतर सफलता के लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने देश की उन्नति, समृद्धि और विकसित भारत के लक्ष्य की सिद्धि की भी कामना की।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में सुशासन, पारदर्शिता, जनकल्याण और राष्ट्रहित को केंद्र में रखकर कार्य किया है। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आज भारत विश्व की प्रमुख शक्तियों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान, नई शिक्षा नीति,

डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, गरीब कल्याण योजनाओं तथा आधारभूत संरचना के विस्तार जैसे अनेक परिवर्तनकारी कदमों ने देश के विकास को नई दिशा दी है। भारत आज आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंचों पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश के करोड़ों नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके मार्गदर्शन में भारत ने सेवा, सुशासन और संकल्प से सिद्धि की भावना के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा और भारत विश्वगुरु के रूप में अपनी गौरवशाली पहचान स्थापित करेगा।

कृषक उन्नति योजना में बदलाव : धान की जगह दलहन-तिलहन और मक्का की खेती पर सरकार का बड़ा प्रोत्साहन

रायपुर। मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और धान पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश में वैकल्पिक फसलों का रकबा बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता के साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार का मानना है कि योजना के नए स्वरूप से किसानों को अधिक प्रभावी लाभ मिलेगा तथा कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। योजना के नए स्वरूप से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

जानें कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप

1. विगत खरीफ में धान की फसल लेने वाले ऐसे कृषक, जिन्होंने आगामी खरीफ में धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराया हो, उन्हें एग्रीस्टेक पर पंजीयन तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर राशि 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाए।

2. खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की फसल लेने वाले कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल तथा एग्रीस्टेक पर पंजीयन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर पूर्ववत् राशि 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाए।

3. विगत वर्ष के फसल एवं रकबे की पुष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वे के डेटा से तथा जहां यह डेटा उपलब्ध न हो वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के डेटा से पुष्टि की जाए।

4. गन्ना फसल के प्रोत्साहन के लिए विभाग द्वारा पूर्ण विचारोपरांत पृथक से प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

5.योजना के प्रचलित निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी करने तथा अन्य अनुषांगिक कार्यवाही करने के लिए प्रशासकीय विभाग (कृषि विकास एवं किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग) को अधिकृत किया जाए।

कुशाभाऊ ठाकरे विवि के कुलपति प्रो मनोज दयाल ने उपमुख्यमंत्री शर्मा से की भेंट

रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति प्रो. डॉ. मनोज दयाल ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार शर्मा से सौजन्य भेंट की। यह मुलाकात विश्वविद्यालय के भविष्य की योजनाओं और राज्य सरकार के सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण रही।भेंट के दौरान कुलपति डॉ. दयाल ने उपमुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और आधारभूत उपलब्धियों से अवगत कराया। चर्चा का मुख्य केंद्र विश्वविद्यालय का सर्वांगीण विका रहा।

डॉ. दयाल ने आगामी दीक्षांत समारोह की तैयारियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इसे प्रदेश की पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षा के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल विद्यार्थियों के सम्मान का अवसर नहीं होगा, बल्कि उद्योग-जगत और मीडिया संस्थानों को एक मंच पर लाकर रोजगार और इंटर्नशिप के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगा। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार शर्मा ने विश्वविद्यालय की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में मीडिया शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने गुणात्मक और संख्यात्मक विकास दोनों में तेजी लाने पर जोर दिया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारिता शिक्षा को तकनीक और उद्योग की

बदलती मांगों के अनुरूप ढालने के लिए हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने पाठ्यक्रम में एआई, डेटा जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जैसे नए विषयों को शामिल करने का सुझाव दिया। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री सुनील शर्मा भी उपस्थित थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के विस्तार, नए विभागों की स्थापना और विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सेल को मजबूत करने से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की। कुलसचिव ने बताया कि विश्वविद्यालय अब शोध, पत्रकारिता नैतिकता और ग्रामीण रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान दे रहा है, ताकि स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच मिल सके। कुलपति डॉ. दयाल ने कहा कि सरकार और विश्वविद्यालय के समन्वय से प्रदेश को कुशल, जिम्मेदार और संवेदनशील पत्रकार मिलेंगे जो लोकतंत्र को मजबूत करेंगे।

महादेव घाट ओवरब्रिज : प्रक्रिया में ही बीत गए दो साल

■ एजेंसी ने नहीं किया अनुबंध, अब री-टेंडर की तैयारी

रायपुर। रायपुर-अमलेश्वर के बीच यातायात दबाव कम करने के लिए प्रस्तावित महादेव घाट ओवरब्रिज परियोजना दो साल पीछे चली गई है। परियोजना के लिए वर्ष 2024 में मंजूरी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी ने नवंबर 2025 में 18 ।66 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। लेकिन वर्क आर्डर जारी करने के बाद केपनी से अनुबंध नहीं हुआ। अब दो साल बाद री-टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

दरअसल, ओवरब्रिड परियोजना के लिए जारी टेंडर के तकनीकी और वित्तीय परीक्षण के बाद विश्रामपुर की एग्रो स्टील वर्क कंपनी को दिसंबर 2025 में करीब 5 प्रतिशत दर पर कार्य आवंटित कर वर्क ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन वर्क ऑर्डर मिलने

के बाद भी कंपनी ने विभाग के साथ अनुबंध नहीं किया।

पीडब्ल्यूडी ने करीब चार माह तक इंतजार किया, लेकिन कंपनी के प्रतिनिधि अनुबंध प्रक्रिया पूरी करने नहीं पहुंचे। इसके बाद विभाग ने सुरक्षा जमा राशि जब्त कर अप्रैल 2026 में दोबारा टेंडर जारी किया। नए टेंडर में चार कंपनियों ने भाग लिया है। तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है, और अब वित्तीय प्रक्रिया चल रही है। अगले 10 दिनों में नई एजेंसी का चयन कर कार्य आवंटन और अनुबंध की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

महादेव घाट के पुराने पुल के समीप खारुन नदी पर बनने वाला यह स्टील ओवरब्रिज 180 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा होगा। निर्माण एजेंसी को कार्य शुरू होने के बाद 18 माह में परियोजना पूरी करनी होगी। पीडब्ल्यूडी के ट्रैफिक सर्वे के अनुसार, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक इस मार्ग पर सबसे अधिक दबाव रहता है। पाटन, अमलेश्वर, दुर्ग-भिलाई और रायपुर के बीच हजारों वाहन रोज जाम का सामना करते हैं।

विभाग की योजना गर्मी के दौरान खारुन नदी का जलस्तर कम होने का फायदा उठाकर नींव और संरचनात्मक कार्य शुरू करने की थी। लेकिन ठेकेदार के पीछे हटने से परियोजना मानसून तक खिंच गई। ऐसे में नदी के भीतर और किनारों पर होने वाले निर्माण कार्य प्रभावित हो सकते हैं, जिससे शुरुआत के बाद भी रफ्तार सीमित रहने की आशंका है।

अधिकारियों के मुताबिक, अमलेश्वर, पाटन रोड और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से आबादी बढ़ रही है। भविष्य के यातायात को देखते हुए अगले 30 वर्षों की जरूरतों के अनुरूप फोरलेन ओवरब्रिज की डिजाइन तैयार की गई है। इस परियोजना का काम पूरा होने के बाद महादेव घाट, चंगोराभाठा, डीडी नगर, संतोषी नगर, प्रोफेसर कॉलोनी, अमलेश्वर, अंजोरा, पाटन रोड क्षेत्र, दुर्ग-भिलाई से रायपुर आने-जाने वालों के साथ नवा रायपुर कनेक्टिविटी से जुड़े हजारों लोगों को लाभ मिलेगा।

गैस एजेंसी मैनेजर से लूट का मामला यूपी से 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर में गैस एजेंसी के मैनेजर से 10 लाख रुपये की लूट के मामले में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश से अंतर्राज्यीय गैंग के दो शातिर लूटेरों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने रकम को हवाला का पैसा समझकर लूट की योजना बनाई थी। पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस जल्द ही करेगी।

दरअसल, टाटीबंध स्थित एचपी गैस एजेंसी के मैनेजर श्रवण साहू को संचालक ने अग्रसेन चौक स्थित एक पार्टी से भुगतान की राशि लेने भेजा था। श्रवण कार से वहां पहुंचे और करीब 10 लाख रुपये लेकर वापस टाटीबंध लौट रहे थे। इसी दौरान एजेंसी को एक उपभोक्ता ने गैस लीकेज की शिकायत की। श्रवण डंगनिया बाजार के पास शीतर माता मंदिर के पीछे गली में ग्राहक के बताए स्थान पर पहुंचे। जैसे ही वह पैसों से भरा बैग लेकर कार से उतरे बाइक सवार तीन युवक पास पहुंच गए। पलक झपकते ही बैग छीनकर आरोपी मौके से फरार हो गए। रायपुर ओवरब्रिज के पास उनकी आखिरी लोकेशन मिली थी। जांच में घटनास्थल और उसके आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस के हाथ लगी। फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां कैद हुई। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई थी।

2-3 दिन में छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून

रायपुर। भीषण गर्मी और उमस से परेशान छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम मानसून दस्तक देने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून हमेशा की तरह बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा, जिससे लोगों को चिपचिपी गर्मी से जल्द निजात मिलेगी।

आमतौर पर देश में मानसून 1 जून को केरल पहुंच जाता है, लेकिन इस साल यह 3 दिन की देरी से 4 जून को केरल पहुंचा। राहत की बात यह है कि केरल में एंट्री के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ा है। वर्तमान में यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को पार करते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 12 से 15 जून के बीच होती है और इस

बार भी समय पर आने का अनुमान है।

रायपुर और मध्य छत्तीसगढ़ में इस समय अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से लोग भारी उमस और पसीने वाली गर्मी से बेहाल हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिनों तक तापमान ऐसा ही रहेगा, इसलिए उमस बनी रहेगी। लेकिन, जैसे ही मानसून बस्तर में एंट्री करेगा, उसके 3 दिन बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी और मौसम सुहाना हो जाएगा।

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने कहा 4 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री केरल में हो चुकी है। 2-3 दिन में बस्तर के रास्ते पूरे प्रदेश में मानसून पहुंचेगा। उससे पहले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। मानसून की एंट्री से पहले मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला के मुताबिक, इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर हवा का एक चक्रवात (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) बना हुआ है। यहां से लेकर मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना तक एक द्रोणिका (मौसम की लाइन) गुजर रही है। इसके असर से छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मानसून आने से पहले ही मौसम बदलेगा। प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

पेड़ों की सुरक्षा और संवर्धन पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता : राज्यपाल डेका

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोक भवन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरुण कुमार पांडे, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री सम्बित मिश्रा, मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त मणिवासगन एस तथा रायपुर वन मंडल के डीएफओ श्री लोकनाथ पटेल ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने शहर और नया रायपुर में लगाए गए वृक्षों के संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया है।

राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही वृक्षों की कटाई की अनुमति दी जाए। राज्यपाल ने शहर में बड़े वृक्षों के पास से ट्री गार्ड हटाने तथा जहां वृक्षारोपण किया गया है, वहां पेड़ों के चारों ओर बने कंक्रीट ढांचे को हटाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ों की जड़ों तक पर्याप्त मात्रा में पानी और हवा पहुंचना

जरूरी है, तभी उनका समुचित विकास हो सकेगा।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण के बाद उनकी देखभाल पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, जो भी पौधे लगाए जाएं, उनकी नियमित निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वे विकसित होकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें। राज्यपाल ने अधिकारियों से शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने और लगाए गए पौधों के जीवित रहने की दर बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास करने को कहा है।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरिये मोदी ने चला मास्टरस्ट्रोक

नीरज कुमार दुबे

मोदी सरकार ने हिंद महासागर में ऐसा दांव चला है, जिसने चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता बढ़ा दी है। ग्रेट निकोबार में बनने वाला भारत का नया सैन्य और आर्थिक हब अब दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी बन चुका है। जिस समुद्री रास्ते से दुनिया का सबसे बड़ा तेल और व्यापार गुजरता है, वहां अब भारत अपनी ताकत का स्थायी पहरा बैठाने जा रहा है। साफ है कि मोदी सरकार हिंद महासागर में भारत को सिर्फ मजबूत नहीं, बल्कि सबसे प्रभावशाली ताकत बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। हम आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष जिस हरित क्षेत्र हवाई अड्डे को मंजूरी दी थी, वह अगले पांच वर्षों में तैयार होने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हवाई अड्डा भारतीय नौसेना के संचालन नियंत्रण में रहेगा। यानी यह केवल नागरिक उड़ानों का केंद्र नहीं होगा, बल्कि हिंद महासागर में भारत की सैन्य शक्ति का नया अग्रिम मोर्चा बनेगा। यह दोहरे उपयोग वाला हवाई अड्डा भारत की समुद्री निगरानी क्षमता, सैन्य पहुंच और त्वरित कार्रवाई की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। हम आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार की यह परियोजना चार बड़े स्तंभों पर आधारित है। इनमें अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, आधुनिक नगर, ऊर्जा संयंत्र और नौसैनिक हवाई अड्डा शामिल हैं। यह पूरा ढांचा भारत को उस समुद्री क्षेत्र में स्थायी उपस्थिति देगा, जहां से दुनिया के दो तिहाई तेल व्यापार और आधा कंटेनर यातायात गुजरता है। ग्रेट निकोबार केवल चालीस किलोमीटर दूर स्थित है उस सिक्स डिग्री चैनल से, जो अदन की खाड़ी से मलक्का जलडमरूमध्य तक फैले समुद्री व्यापार मार्ग का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। यही वह इलाका है जहां चीन लगातार अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में कई बाहरी ताकतें आर्थिक और सैन्य दबदबा बनाने में जुटी हैं। ऐसे में मोदी सरकार का यह कदम भारत को दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में निर्णायक बढ़त देगा। यानि अब भारत इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा साझेदार और संकट के समय सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाली ताकत के रूप में उभरेगा। रक्षा सूत्रों का साफ कहना है कि यह परियोजना तीस वर्ष पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन पिछली सरकारों की सुस्ती और दूरदृष्टि की कमी के कारण भारत ने बहुमूल्य समय गंवा दिया। अब मोदी सरकार उस रणनीतिक भूल को सुधार रही है। यह परियोजना भारत को अपने सैन्य संसाधनों की तेज आवाजाही, अग्रिम रसद आपूर्ति और समुद्री निगरानी में अभूतपूर्व क्षमता देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेट निकोबार के आसपास समुद्र में विशाल हाइड्रोकार्बन भंडार भी हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी ऐतिहासिक साबित होगी। यानी यह केवल सैन्य ताकत का सवाल नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी बड़ा आधार बनेगी।साथ ही मोदी सरकार ने उन आलोचनाओं को भी करारा जवाब दिया है, जिनमें इस परियोजना को केवल व्यावसायिक योजना बताकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। रक्षा सूत्रों ने साफ कहा है कि इसे केवल कारोबारी परियोजना कहना भौगोलिक अज्ञानता का प्रमाण है। यह परियोजना सामरिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत के भविष्य की धुरी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी परियोजनाएं पूरी पारदर्शिता और विधिवत ठेका प्रक्रिया के तहत संचालित की जा रही हैं। हम आपको बता दें कि परियोजना के विभिन्न हिस्सों पर तेजी से काम चल रहा है। कंटेनर बंदरगाह के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के 12 साल पूरे

डॉ. मोहन यादव

भारत के इतिहास में श्री नरेन्द्र मोदी का लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनना देश के लिये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लगातार 3 बार सत्ता में आना श्री मोदी की कार्यप्रणाली, सभी को साथ लेकर चलना और देश को सुरक्षा देने के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही उनकी विशेषता रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इन्हीं विशेष खूबियों ने नये भारत के निर्माण का स्वर्णिम अध्याय लिखा है।

यशस्वी श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब देश की जनता ने केवल एक सरकार नहीं चुनी थी, बल्कि शासन की एक नई कार्यशैली और राजनीतिक संस्कृति की अपेक्षा भी व्यक्त की थी। बारह वर्ष बाद इस यात्रा को केवल योजनाओं, आंकड़ों और उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि उस व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर समझना अधिक उचित होगा, जिसने शासन की सोच को प्रभावित किया। यदि इन बारह वर्षों को तीन शब्दों में समेटना हो, तो वे शब्द होंगे— सेवा, सुशासन और संकल्प।

प्रधानमंत्री जी की सोच में सेवा का अर्थ केवल कल्याणकारी योजनाएं चलाना नहीं रहा, बल्कि सेवा का अर्थ शासन स्वयं को जनता का संरक्षक और सेवक के रूप में हैं। इस दृष्टि से पिछले बारह वर्षों में शासन की प्राथमिकताओं में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की उन्होंने चिंता की है। गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग को केवल वोट बैंक के रूप में नहीं, बल्कि विकास प्रक्रिया को केंद्र में रखने की कोशिश की जो सफलता के शिखर तक जा पहुंची। यही सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद में भी दिखाई देती है। मोदीजी की सरकार ने बार-बार यह संदेश दिया है कि विकास का वास्तविक अर्थ तब है, जब उसका लाभ समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे।

प्रधानमंत्री जी की प्रमुखता में सुशासन एक प्रमुख केन्द्र बना। सुशासन का अर्थ सरकार को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाना है। डिजिटल तकनीक का उपयोग इसी दर्शन का हिस्सा था। तकनीक को केवल आधुनिकता का प्रतीक नहीं, बल्कि सुशासन का माध्यम माना गया। शासन और नागरिक के बीच की दूरी कम करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा निर्णयों को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार

प्रयास किये गये जो लगातार जारी हैं। इसका मूल ध्येय यह है कि आम नागरिक को सरल और सहज तरीके से उसके अधिकार मिलें और योजनाओं का लाभ सहजता से मिल सके।

मुझे यह बताते हुये खुशी है कि श्री मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकतंत्र में संवाद को आवश्यक मानते हैं। उनका समय-समय पर अलग-अलग वर्गों से सीधा संवाद करना और उन्हें मार्गदर्शन देना अदभुत है। वे युवाओं के लिये अभिभावक की भूमिका भी निभाते हैं। छात्र-छात्राओं को परीक्षा के समय आत्म मजबूत करने के लिये परीक्षा पर चर्चा जैसे विषयों पर उनका संवाद लगातार जारी रहता है। इसी क्रम में उनकी मन की बात कार्यक्रम को पूरा देश बड़े आत्मीय तरीके से आत्मसात करता है। यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की विशेषता है।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी की सरकार की कार्यशैली में यह स्पष्ट दिखाई दिया देता है कि बड़े निर्णयों से बचने के बजाय उन्हें समाधान तक कैसे पहुंचाया जाए? दरअसल, इसे ही निर्णायक नेतृत्व कहते हैं। यह निर्विवाद है कि निर्णय लेने की क्षमता इस शासनकाल की प्रमुख पहचान रही है।

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में मोदी सरकार ने विकसित भारत को राष्ट्रीय संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। यह संकल्प केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। इसके भीतर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की भावना भी जुड़ी हुई है। पिछले बारह वर्षों में बार-बार यह संदेश दिया गया कि भारत को केवल विकासशील राष्ट्र के रूप में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे विश्व की अग्रणी शक्तियों में स्थान प्राप्त करना चाहिए। यह दृष्टिकोण भारतीय समाज में एक नए आत्मविश्वास का निर्माण करता है।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमने भी विकसित मध्यप्रदेश का सपना देखा। यह बताते हुए मन भाव-विभोर है कि मोदीजी का हर कदम पर हर निर्णय पर मार्गदर्शन, स्नेह और आशीर्वाद मिला। चाहे वर्षों से लंबित केन-बेतवा और पार्वती -कालीसिंध -चंबल लिंक परियोजना हो या पीएम मित्र पार्क, उन्होंने आगे बढकर परेशानियों को दूर किया। उनके जैसा नेतृत्व दुर्लभ है। हाल ही में देश के सात राज्यों में पीएम मित्र पार्क बनाने का निर्णय हुआ, तो उस सूची में मध्यप्रदेश को भी रखा गया। यह अति प्रसन्नता का विषय है कि अब तक सिर्फ मध्यप्रदेश में ही पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन हुआ है और यह गौरव का विषय रहा कि धार में पार्क के भूमिपूजन में प्रधानमंत्री जी शामिल हुए। यह सब मध्यप्रदेश से उनके विशेष लगाव का परिणाम ही है।

प्रदेश में साइबर तहसील का सफल क्रियान्वयन हो या भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल, सब प्रधानमंत्रीजी के स्नेह -आशीर्वाद -मार्गदर्शन का ही परिणाम है। आज प्रदेश में नौ एयरपोर्ट हैं, तो इसके पीछे भी उनका ही मार्गदर्शन है। आज हमारा मध्यप्रदेश नक्सल मुक्त है, तो इसके पीछे उनका ही दिशा-निर्देश है। उन्होंने समय - समय पर समझाया, तो चेताया भी। उन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोली से दो पर जो लोग बंदूक - हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था भी हो। उनकी सलाह-चेतावनी का ही सुफल है कि आज मध्यप्रदेश लाल सलाम को आखिरी सलाम कह चुका है।

प्रधानमंत्रीजी के मार्गदर्शन में ही मध्यप्रदेश में उद्योगों का जाल बिछ रहा है, लाखों करोड़ का निवेश हो रहा है। फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में शामिल होना, उनका विशेष स्नेह ही तो दर्शाता है। उन्होंने हमें संवेदना की सीख दी है। उनकी सीख ही थी कि हमने अपने शुरूआती निर्णयों में ही इंदौर के हुकुमचंद मिल के कामगारों को उनका बकाया अधिकार दिलवाने में सफलता हासिल की। कामगारों को चेक सौंपने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को प्रधानमंत्रीजी ने वर्चुअली संबोधित भी किया था।

मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों में अग्रणी सरकारी कालेजों को प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना हो या हाइवे का विकास हो, हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर रूचि दिखाई, मार्गदर्शन -मदद और स्नेह देते रहे। मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि वे कालजयी, त्रिकालदर्शी नेता हैं। हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक मोदीजी के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता सांस्कृतिक चेतना का पुनर्रूत्थान भी है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आधुनिकता को अपनाया, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर संकोच दिखाई दिया।

पिछले बारह वर्षों में भारतीयता, विरासत और सभ्यता पर गर्व करने का भाव अधिक मुखर होकर सामने आया है। यह विचार केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक यात्रा को आधुनिक राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का प्रयास भी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी का पुनर्विकास हो, या विश्व मंचों पर भारतीय परंपराओं और योग का प्रचार—इन सभी के पीछे सांस्कृतिक आत्मविश्वास का वही भाव दिखाई देता है। उनसे प्रेरणा प्राप्तकर मध्यप्रदेश भी अपनी विरासत को संजो रहा है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था या सेना में नहीं होती। उसकी शक्ति उसके आत्मविश्वास में भी होती है। इस दृष्टि से सांस्कृतिक पुनर्जागरण मोदीजी के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 12 वर्षों को यदि केवल योजनाओं और आंकड़ों से समझने का प्रयास किया जाए, तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। इन 12 वर्षों का वास्तविक महत्व उस सोच में है, जिसने शासन को सेवा से, प्रशासन को सुशासन से और राजनीति को संकल्प से जोड़ने का सफल प्रयास किया है। यह कालखंड भारत के आत्मविश्वास, आकांक्षाओं और राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण का कालखंड रहा है। यह नए भारत की आधारशिला है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

प्रशंसनीय बात यह है कि इसकी नाक लम्बी और शिर मनुष्य का सा है।

(ता0 31-8-25 के : हिन्दू सर्वस्व- हरिद्वार से)

तीन टांग का अर्धनारीश्वर

देहली में आठ वर्ष की आयु का एक ऐसा बालक है कि जिसकी तीन टांगें हैं। इसका आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का है!

(ता0 26-8-1925 हिन्दू सर्वस्व से)

रोछ और गधे का मिक्स

लाहोर 16 जून। लाहौर जिले के एक बढ़ई की स्त्री ने एक लड़की को जन्म दिया है जिसका भालू जैसा चेहरा और गधे जैसे कान हैं। उसकी जीभ गर्दन से सटी हुई है। लड़की जन्म लेने के कुछ घण्टों पीछे मर गई।

(ता0 21-6-1626 के हिन्दू संसार देहली से)

जब कि मानव स्त्रियों के पेट से पशुओं के आकर प्रकार के अद्भुत बच्चे अब भी पदा होते हैं तब अतीत काल में गाय के पेट से मनुष्याकृति बच्चे का पैदा हो जाना किस न्याय से सृष्टि नियभ के विरुद्ध जंचता है, यह दुरंगी हमारी समझ में नहीं आती!

कदाचित् महाशयों को गोकर्ण का पूर्ण पण्डित होकर मनुष्यायु भोगना अखरता हो तो उन्हें महात्मा-प्रदत्त उस फल का भी तो ध्यान करना चाहिये जो कि योग-विद्या के चमत्कारों से परिपूर्ण होने के कारण अमुक अमुक गुणसम्पन्न दीर्घायुः सन्तान प्रदान करमे की सामर्थ्य रखता था। इसलिये योग-शक्ति के प्रभाव का तथा प्रकृतिदेवी के वैलक्षण्य का विचार करते हुये उक्त कथा का मनन करना चाहिये। जो बात हमारी तुच्छ बुद्धि में न समा सके उसके लिये सृष्टिनियमविरुद्ध होने का फतवा दे देना तो निरी ग्रज्ञता है।

क्रमशः ...

रामप्रसाद बिस्मिल

विवेक शुक्ला

स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। उनके पिता एक रामभक्त थे, जिसके कारण उनका नाम र से रामप्रसाद रख दिया गया।

19 वर्ष की आयु में बिस्मिल ने क्रांति के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा। अपने 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई किताबें भी लिखीं और उन्हें प्रकाशित कर, प्राप्त रकम का प्रयोग उन्होंने हथियार खरीदने में किया। बिस्मिल उनका उपनाम था, जो कि उर्दू भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है आत्मिक रूप से आहत। रामप्रसाद बिस्मिल ने राम और अज्ञात नाम से भी लेखन किया। 9 अगस्त, 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देशभक्तों ने रेल विभाग की ले जाई जा रही संगृहीत धनराशि को लूटा। गार्ड के डिब्बे में लोहे की तिजोरी को तोड़कर आक्रमणकारी दल चार हजार रुपये लेकर फरार हो गए। इस डकैती में अशफाकउल्ला, चन्द्रशेखर आज़ाद, राजेन्द्र लाहिड़ी, सचीन्द्र सान्याल, मन्मथनाथ गुप्त, रामप्रसाद बिस्मिल आदि शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र मुकदमे ने काफी लोगों का ध्यान खींचा।

चौरीचौरा कांड के बाद अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके कारण देश में फैली निराशा को देखकर उनका कांग्रेस के आजादी के अहिंसक प्रयत्नों से मोहभंग हो गया। फिर तो नवयुवकों की क्रांतिकारी पार्टी का अपना सपना साकार करने के क्रम में बिस्मिल ने चंद्रशेखर 'आजाद' के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ गोरों के सशस्त्र प्रतिरोध का नया दौर आरंभ किया लेकिन सवाल था कि इस प्रतिरोध के लिए शस्त्र खरीदने को धन कहां से आये? इसी का जवाब देते हुए उन्होंने नौ अगस्त, 1925 को अपने साथियों के साथ एक ऑपरेशन में काकोरी में ट्रेन से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना लूटा तो थोड़े ही दिनों बाद 26 सितंबर, 1925 को पकड़ लिए गए और लखनऊ की सेंट्रल जेल की 11 नंबर की बैरक में रखे गए। बिस्मिल को छह अप्रैल 1927 को काकोरी कांड का अभियुक्त मानते हुए सजा सुनाई गई। वे पहले लखनऊ जेल में रखे गए। इसके बाद उन्हें अंग्रेजों ने 10 अगस्त को 1927 को गोरखपुर जेल भेज दिया। यहां वे कोठरी संख्या सात में रहते थे। इस कोठरी को अब बिस्मिल कक्ष के नाम से जाना जाता है।

सभी प्रकार से मृत्यु दंड को बदलने के लिए की गई दया प्रार्थनाओं के अस्वीकृत हो जाने के बाद बिस्मिल अपने महाप्रयाण की तैयारी करने लगे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में गोरखपुर जेल में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। फांसी के तख्ते पर झूलने के तीन दिन पहले तक वह इसे लिखते रहे। उन्होंने कुल 11 पुस्तकें लिखी थीं। वे इन पुस्तकों को स्टॉल लगाकर खुद भी बेचते थे। उनकी पुस्तकों में स्वाधीनता का अंश होता था। यही कारण है कि उनकी पुस्तकों को लोग ज्यादा पसंद करते थे। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि उन्होंने क्रांतिकारी बनने के बाद पहला तमंचा अपनी किताब की बिक्री से मिली राशि से ही खरीदा था।

भारत को किस बड़े जंग के लिए तैयार कर रहा रूस?

अभिनय आकाश

वैश्विक हालात इस वक्त किसी चेसबोर्ड की तरह हैं, जहां भारत एक बार फिर से चेकमेट की तरफ है। यहां हर पल नए बदलाव हो रहे हैं, लेकिन भारत हर मोड़ पर खुद को बलवान साबित कर रहा है। एक तरफ ट्रंप भारत को टैरिफ वाली धमकी देते हैं। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन हैं जो भारत को सबसे एडवांस फाइटर जेट साथ बनाने का ऑफर दे रहे हैं। भारत अपनी स्वदेशी तकनीक और रक्षा बजट में भारी बदलाव कर रहा है। जिससे चीन और पाकिस्तान का गला अभी से सूख रहा है। दुनियाभर को आंख दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ डील करने की बातों को दोहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का बारूदी पावर अब शिफ्ट हो रहा है। भारत को दी गई धमकी अब ट्रंप को महंगी पड़ने वाली है। क्या ट्रंप को ट्रेलर दिखने लगा है। क्या रूस भारत की दोस्ती अमेरिका को करारा जवाब देने की तैयारी कर रही है। स्ट्रैटजिक ऑटोनॉमी का ये अध्याय दुनिया को बता रहा है कि भारत किसी के दवाब में नहीं आता है। आज का एमआरआई इसी विषय पर करेंगे कि भारत कैसे मजबूत हो रहा है और अमेरिका भारत की तरफ डील को लेकर आंखें उठाकर देख रहा है।

भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग की लंबी कहानी में अब एक नया अध्याय जुड़ सकता है। राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन ने भारत को एक लड़ाकू गिफ्ट देने की बात कही है। पुतिन ने एक बयान में कहा है कि वह भारत के साथ मिलकर सुखोई एसयू 57 को डेवलप करना चाहते हैं। एसयू 57 एक फिफ्थ जनरेशन का सेल फाइटर जेट है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर इसको डेवलप करना चाहते हैं। भारत और रूस ने मिलकर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की बात थी। स्टेल्थ फाइटर जेट होना था उसको डेवलप करने की बात हुई थी। 2017-18 के आसपास कुछ कारणों से बात नहीं बनी। भारत ने खुद को इस प्रोग्राम से अलग कर दिया। एसयू 57 वही प्रोग्राम

का हिस्सा है। फरवरी 2025 में यह जेट भारत आया था। एरो इंडिया एयर शो में ये जेट आया था और उस समय भी बातें चली थी कि रूस ने कहा है कि हम आपको प्रोडक्शन देंगे। जैसे कि सुखोई सु 30 के मामले में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया जेट है। भारत रूस में एसयू57 को लेकर पहली बार एरो इंडिया में ऑफर आया। इसके बाद भी कई बार यह खबरें आती रही। रूसी मीडिया आउटलेट से भी, भारतीय मीडिया और फॉरेन मीडिया कई सारे ने इसको रिपोर्ट किया कि रूस बार-बार हमें ऑफर कर रहा है बैक चैनल से, फ्रंट चैनल से और अब जाकर प्रेसिडेंट की तरफ से ऑफर आया है।

भारत और रूस के बीच पहली सुखोई डील 30 नवंबर 1996 को हुई थी। इस डील की कुल कीमत 1.462 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी उस समय के हिसाब से लगभग 7155 करोड़ थी। शुरू में 50 विमानों की डील हुई थी जिनमें 40 एसयू 30 के और 10 एसयू 30 एमकेआई शामिल था। यह डील रूस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील थी। शुरू में एसयू 30 के आया लेकिन बाद में भारत ने एसयू30 एमकेआई इंडिया स्पेसिफिक वर्जन की मांग कर दी। 1998 से 2000 के बीच सुखोई की पहली खेप भारत पहुंची। इस डील के बाद भारत ने कई फॉलो ऑन ऑर्डर दिए जिससे कुल संख्या 270 से ज्यादा हो गई। इस डील ने भारत रूस रक्षा संबंधों को नया आयाम दिया। पहले भारत मुख्य रूप से मिग 21 मिग 29 पर निर्भर था। एसयू 30 एमकेआई ने इंडियन एयरफोर्स को हैवी मल्टी रोल फाइटर कैपेबिलिटी दी। भारत के पास इस वक्त सुखोई के दो वर्जन हैं। पहला एसयू 30 एमकेआई यह भारत के लिए कस्टमाइज वर्जन है और दुनिया के सबसे कैपेबल ट्विन सीटर फाइटर्स में से एक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में इसका लाइसेंस प्रोडक्शन कर रहा है। दूसरा है सुपर सुखोई सुपर 30 यानी एसक्यू30 का अपग्रेडेड वर्जन। इसके अंदर भारतीय विरुपक्षा रडार लगा है। साथ ही बेहतर रडार वार्निंग और डिजिटल सिस्टम लगा है। अपग्रेड करने का मुख्य लक्ष्य इसे 4.5 प्लस जनरेशन स्तर का बनाना और इसका जीवन 20 से 25 साल बढ़ाना था।

भारत इस वक्त दुनिया भर में हथियारों के सबसे बड़े खरीदार में से एक है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान भारत को एफ 35 की पेशकश की थी। अब पुतिन के नए प्रस्ताव के बाद माना जा रहा है कि रूस इन पुरानी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन के इस ऑफर के ठीक बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी बात कही और डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि वो भारत से डील करने के लिए बेताब है। ट्रंप एक तरफ तो भारत के खिलाफ दबाव की रणनीति अपनाते हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की तारीफ कर मामले को बैलेंस करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन पुतिन भी एक मझे हुए राजनेता हैं और वो किसी भी कीमत पर अपने पुराने साथी भारत के साथ रिश्ते को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। पुतिन ने अपने संबोधन के दौरान सुखोई डील की बात की। साथ ही भारत को लेकर कई और अहम बातें कही। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा भारत एक मजबूत और स्वतंत्र देश है जो अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसला लेता है। दोनों देशों के रिश्ते दशकों पुराने हैं। कई कोशिशों के बावजूद यह रिश्ता लगातार मजबूत हुआ है। भारत का अपने हितों के मुताबिक दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ संबंध विकसित करना स्वाभाविक है। भारतीयों की मेहनत और प्रतिभा के बदौलत भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। पुतिन ने भारत की आर्थिक प्रगति का क्रेडिट पीएम मोदी को दिया। अनुमान है कि भारत रूस व्यापार आगे बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। व्लादमीर पुतिन की ये बातें और सुखोई 57 का ऑफर डोनाल्ड ट्रंप की चिंताओं को बढ़ाने के लिए काफी है। साथ ही यह बात भारत के दो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की बेचैनी को सातवें आसमान पर ले जाएंगी।

अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डोमिनेंस फाइटर जेट लॉक हीड मार्टिन एफ 52 रैप्टर है। सबसे एडवांस्ड मल्टी रोल फाइटर एफ35 लाइटनिंग टू देने का ऑफर अमेरिका पहले ही भारत को दे चुका है। चीन के पास जे 20 माइटी ड्रैगन फाइटर जेट है और यह चीन का फिफ्थ जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट है। यह एशिया पेसिफिक में सबसे ताकतवर माना जाता है। लेकिन अब रूस ने भारत को सुखोई यानी कि एसयू 57 और साथ में उसे बनाने तक का ऑफर दे दिया। यहां तक कि रूस ने कहा कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में भारत के लिए यह डील काफी फायदेमंद हो सकती है। सुखोई 57 अमेरिका के एफ 22 और एफ 35 का रूसी जवाब माना जाता है। आखिर रूस के इस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में क्या खास है कि दुनिया भर के कई मुल्क इसे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन रूस इसे बनाने का ऑफर भी भारत को दे रहा है। सुखोई 57 दुनिया के सबसे मेन्यूरेबल फाइटर जेट्स में से एक है। 3डी थ्रस्ट इंजन और रिलैक्स्ड स्टेबिलिटी डिजाइन की वजह से यह एक्सट्रीम मूवमेंट्स कर सकता है। जिसकी वजह से क्लोज कॉम्बैट में यह सुखोई 57 बेहद खतरनाक साबित हो जाता है। इसकी दूसरी सबसे खास बात ये कि सुपर क्रूज क्षमता वाला यह फाइटर जेट ये मैक 1.3 की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। इससे ईंधन की बचत होती है, रेंज बढ़ती है और मिसाइलों का प्रभाव इसमें काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मिसाइलों की प्रभावी दूरी इसमें बढ़ जाती है। अधिकतम स्पीड इसकी मैक टू मानी जाती है।

आज का इतिहास

1921 ब्राजील में महिलाओं को चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया।
1932 मोहम्मद अली अल-अबिद सीरिया के पहले राष्ट्रपति बने।
1934 संयुक्त राज्य अमेरिका में पारस्परिक टैरिफ अधिनियम लागू किया गया।
1935 पहली बार एडविन आर्मस्ट्रांग ने एफएम का प्रसारण किया।
1940 यूरोपीय देश इटली ने मित्र देशों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की।
1942 अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लैंड-लीज समझौते पर हस्ताक्षर किये।
1955 पहले मैग्निशियम जेट हवाई जहाज ने उड़ान भरी।
1955 पियरे लेवेग और लांसमैकलिन के 24 घंटे चलने के दौरान ले मैनस्पोर्ट्स कार धीरज की दौड़ के 23 वें भाग के दौरान 80 से अधिक लोग मारे गए थे।
1956 छह दिवसीय गैल ओया दंगों, स्वतंत्र श्रीलंका में तत्कालीन श्रीलंका के तमिलों को लक्षित करने वाले पहले जातीय दंगों की शुरुआत हुई, अंत में कम से कम 150 लोगों की मृत्यु और 100inj चोटों के परिणामस्वरूप।
1960 पाकिस्तान के मुल्तान में एक शादी के रिसेप्शन में तीस लोग एक छत के गिरने से मारे गए।
1963 वियतनामी भिक्षु थिच क्वांग ड्यूक ने दक्षिण वियतनामीप्रवासी नगो दीन्ह के प्रशासन द्वारा बौद्धों के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए खुद को इंसेनॉन में जला दिया।
1963 अलबामा विश्वविद्यालय को राज्यपाल पद से हटा दिया गया क्योंकि अलाबामा के गवर्नर जॉर्ज वालेस ने एक ऑडिटोरियम में खुले तौर पर रूकावट को रोकने के बाद कदम रखा।
1964 ग्रीस ने साइप्रस से तुर्की के साथ सीधी बातचीत को खारिज किया।
1968 लॉयड जे। ओल्ड ने पहली कोशिका की सतह के एंटीजन को अलग-अलग वंशों की कोशिकाओं को अलग करने की पहचान की, जो सेल सतह के एंटीजन की अवधारणा को पेश करता है जो विभिन्न प्रकार के सेल को अलग कर सकता है।
1985 रूसी अंतरिक्ष जांच वेगा 1 शुक्र पर उतरा। मॉड्यूल, एक 1500 किलो, 240 सेमी व्यास के गोले में एक सतह लैंडर और एक गुब्बारा एक्सप्लोरर शामिल था।
1987 मार्गरेट थैचर 160 वर्षों में लगातार तीसरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनी।
2012 अफगानिस्तान में भूकंप के झटके के बाद हुए भूस्खलन में 80 लोगों की मौत।

भतीजे अभिषेक के मोह में ममता दीदी की पार्टी बिखर गयी!

मनोज कुमार अग्रवाल

कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जिते यानि इंसान का अपने ज्ञान और ताकत पर अधिक घमंड पतन का कारण बन जाता है ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ है दीदी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को वनमैन शो बतौर माना और अपने साथियों को फोलौवर समझा यही उनके खिलाफ असंतोष का कारण बन गया दीदी अपने पार्टी के कुनवे को ही संभाल कर नही रख सकी सत्ता से बाहर होते ही उनके खास सिपहसलार ही उनके खिलाफ मुखर हो गए हैं दरअसल भतीजे अभिषेक बनर्जी का मोह और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की चाहत इस असंतोष के पीछे की खास वजह बन गई।

आपको बता दें पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीतिक और कानूनी परेशानियां मई 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद से लगातार बढ़ रही हैं। पार्टी के भीतर बड़ी बगावत और कानूनी मुकदमों ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।ताज़ा घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस में एक बड़ा राजनीतिक संकट सामने आया है। टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने बगावत कर दी है और एनडीए के साथ गठबंधन करने की इच्छा व्यक्त की है।इस विभाजन और दलबदल से जुड़ी जानकारी के अनुसार बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र भेजकर संसद में अलग बैठने और मान्यता देने की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम में टीएमसी सांसद काकुली घोष, सुवेंदु अधिकारी और अन्य नेताओं का नाम सामने आ रहा है।

आपको पता रहे कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपने 28 साल के इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक संकट से जूझ रही है। पार्टी के 58 विधायकों ने बागी रुख अपनाते हुए निष्कासित नेता ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है, जिसे विधानसभा स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी है। पार्टी पर पकड़ ढीली होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संकट के बीच ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई हाई-लेवल बैठक में 80 में से केवल 8 विधायक और 41 में से सिर्फ 6 सांसद ही शामिल हुए। ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों ने इस बैठक से दूरी बना ली, जो उनके नेतृत्व को एक सीधा चैलेंज माना जा रहा है। राजनीतिक मोर्चे के साथ-साथ ममता बनर्जी अब कानूनी पचड़े में भी फंस गई हैं। चुनाव के दौरान दिए गए उनके बयानों और बांग्लादेश में हुई राजनीतिक हत्या के मामले को केंद्र सरकार से जोड़ने को लेकर उनके खिलाफ सिलीगुड़ी और कोलकाता में राजद्रोह और हेट स्पीच की शिकायतें व पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसे देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है।

आपको बता दें सत्ता हाथ से जाने के बाद जमीनी स्तर पर भी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भगदड़ मची हुई है। उनके बेहद करीबी माने जाने वाले कोलकाता के मेयर फिरहाद

हकीम और बिधाननगर की मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा राज्यभर में 100 से ज्यादा टीएमसी पार्षदों और स्थानीय नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है।

ममता बनर्जी को अपने ही गढ़ भवानीपुर सीट से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी के हाथों 15,105 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। राज्य में 15 साल पुराने टीएमसी शासन का अंत हो गया है और सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा की नई सरकार का गठन हो चुका है। ममता बनर्जी इन सभी विपरीत हालातों के खिलाफ सड़कों से लेकर हाइकोर्ट तक कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हैं।

आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम एक माह पूर्व 4 मई को सामने आए थे। इनमें ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को निराशा का मुंह देखना पड़ा था। 294 सीटों वाली इस विधानसभा में उसे 80 सीटें ही मिली थीं। इस तरह 15 वर्ष तक प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं ममता का शासन खत्म हो गया था। ममता ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी। लम्बी अवधि तक वह इसके साथ जुड़ी रहीं, परन्तु 28 वर्ष पूर्व 1998 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) का गठन किया था और कम्युनिस्ट पार्टियों के तीन दशकों से भी अधिक प्रदेश में चले आ रहे लम्बे शासन को खत्म करने के लिए बड़ी दिलेरी और दृढ़ता से उसका मुकाबला किया था। इस समय लोकसभा में इनके 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं, परन्तु विगत लम्बी अवधि से इस पार्टी के भीतर ममता की तानाशाही और टकराव वाली नीतियों के कारण असंतोष और असहमति चल रही थी, परन्तु उनकी प्रशासन पर सख्त पकड़ और कठोर फैसलों से यह बग़ावत अंदर-अंदर ही सुलगती रही थी।

ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपने साथ राजनीति में लाकर उसे अधिक शक्तियां दे दी थीं। बनर्जी के काम करने के ढंग-तरीके से भी पार्टी गलियारों में असंतोष था, जिसके संबंध में ममता को लगातार उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा अवगत करवाया जाता रहा था परन्तु ममता ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। अपनी ताकत के दम पर उन्होंने बड़ी राष्ट्रीय नेता होने का भ्रम भी पाल लिया था, जिस कारण राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों ही पार्टियों द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन की वह सदस्य ज़रूर बनी रही थीं, परन्तु इसमें शामिल अलग-अलग पार्टियों के सभी नेताओं से ऊंचा कद होने का भ्रम उन्होंने पाल रखा था। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी किसी भी सहयोगी पार्टी के साथ गठबंधन करने से इन्कार कर दिया था। उनके शासन के समय प्रदेश की आर्थिकता भी बेहद कमज़ोर हो गई थी और यह पूरी तरह कर्ज में डूब चुका था। केन्द्र के साथ लगातार टकराव रहने के कारण और उद्योग को समर्थन न मिलने के कारण प्रदेश की आर्थिकता डावांडोल हो गई थी। इसके साथ ही बेरोज़गारी की दर भी बढ़ चुकी थी, परन्तु पिछला पूरा समय केन्द्र और अन्य पार्टियों के साथ टकराव बने रहने के कारण भी उनकी प्रशासनिक तौर पर पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। ऐसी स्थिति लोगों के भीतर निराशा में बदलती गई। लगातार सरकार विरोधी भावनाओं के बढ़ने का अनुमान लगाने में वह असमर्थ रहीं और न ही वह दीवार पर लिखे को पढ़ सकीं, जिस कारण उन्हें चुनाव में निराशा का मुंह देखना पड़ा।

हार के बाद भी उन्होंने खुले मन से आत्म-मंथन करने की बजाए अपनी पार्टी के भीतर असंतोष को अनदेखा किए रखा जो अंत में उनके लिए हानिकारक सिद्ध हुई। आंतरिक यह चिंगारी उस समय लपटें बन गई, जब उन्होंने ज्यादातर पार्टी नेताओं को अनदेखा करके अभिषेक बनर्जी के कहने पर विधानसभा में विपक्ष के नेता के लिए सैमन देव का नाम स्पीकर को भेज दिया, परन्तु ज्यादातर विधायक इस पद के लिए रिताव्रता बनर्जी के पक्ष में थे, परन्तु ममता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इस पद के लिए स्पीकर को विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र भेज दिया, जिस कारण ज्यादातर नेताओं ने बग़ावत का मार्ग अपना लिया। इस मामले को लेकर ही बुधवार को पार्टी के 80 विधायकों में से 59 विधायकों ने विधानसभा के स्पीकर से सम्पर्क किया। अपने हस्ताक्षरों वाला पत्र उन्हें सौंपा और अपने गुट को असली तृणमूल कांग्रेस बताया। पार्टी के 28 वर्ष के के इतिहास में ममता पर पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है।

दूसरी तरफ भाजपा को बड़ी जीत प्राप्त होने के कारण उसके नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के बागियों के साथ कोई भी समझौता करने से इंकार कर दिया है। रिताव्रता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वामपंथी विद्यार्थी संगठन से की थी। 34 वर्ष की उम्र में वह राज्यसभा के सदस्य बन गए थे और बाद में वह टी.एम.सी. में शामिल हो गए थे। ममता ने ही उन्हें वर्ष 2024 में राज्यसभा में भेजा था। विधानसभा चुनाव में वह उलबेरिया सीट से विधायक चुने गए हैं। चाहे ममता ने इस बड़ी चुनौती के समक्ष भी अपना हौसला कायम रखते हुए इन बागियों और भाजपा को ललकारा है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा विरोधी पार्टियों से सम्पर्क करने की बात भी की है, परन्तु अब यह देखना शेष होगा, कि वह निकट भविष्य में प्रदेश और देश की राजनीति में किस तरह विचरण करेंगी।स्पष्ट है कि आज की राजनीति में साम दाम दंड भेद सब का चलन बढ़ गया है सत्ता में सबको समेट रखने की ताकत है लेकिन सत्ता से बाहर होते ही अपने सगे साथियों की हकीकत सामने आ जाती है कि उनके दिल में कितना खार छुपाए बैठे थे यह बदलते दौर की राजनीति की नंगी तस्वीर है इस को स्वीकार करना ही होगा।

राजनीति में एक नए राहुल का उदय!

हरीश गुप्ता

केरल में वीडी सतीशन और कर्नाटक में डी.के। शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद पर सुचारु रूप से पदोन्नत करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्टी के भीतर से प्रशंसा मिली है। कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें निर्णायक लेकिन संयमित राजनीतिक प्रबंधन का श्रेय दिया है। केरल में, राहुल गांधी ने सतीशन को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन देकर कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, जबकि व्यापक रूप से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे अपने करीबी विश्वासपात्र के.सी। वेणुगोपाल का पक्ष ले रहे हैं। इस निर्णय ने व्यक्तिगत संबंधों पर राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने की उनकी इच्छा को प्रदर्शित किया। कर्नाटक में, सिद्धारमैया के सुचारु रूप से पद छोड़ने और शिवकुमार को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका को गुटबाजी से ग्रस्त पार्टी में सफल उत्तराधिकार प्रबंधन के एक दुर्लभ उदाहरण के रूप में देखा गया। हालांकि, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह बदलाव बहुत पहले ही शुरू हो गया था। वर्षों से राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता था जो वरिष्ठ सहयोगियों और सोनिया गांधी की बात धैर्यपूर्वक सुनते थे, अक्सर सामूहिक निर्णयों को स्वीकार करते थे और राजनीतिक आलोचनाओं को सहते थे। फिर भी, 6 मई को उन्होंने अचानक डीएमके से संबंध तोड़कर और तमिलनाडु में विजय की टीवीके के साथ कांग्रेस का गठबंधन करके एक नया मोड़ ले लिया। इस कदम से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। आलोचकों ने उन पर अपने लंबे समय से चले आ रहे सहयोगी को धोखा देने का आरोप लगाया, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही डीएमके से अलग होने की वकालत कर रहे थे। डीएमके नेतृत्व की जोरदार पैरवी के बाद उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया। फैसला स्वीकार करने के बाद, राहुल ने नतीजे घोषित होते ही तेजी से कार्रवाई की। केरल और कर्नाटक में बाद में हुए नेतृत्व के चुनाव ने इस धारणा को और पुख्ता कर दिया कि अब वे अधिक दृढ़ता से सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन में पहले मिली असफलताओं के बाद, राहुल गांधी पिछली गलतियों को न दोहराने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी उपलब्धि तब मिली जब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद सत्र के दौरान समन्वय समिति की बैठकें विपक्ष के प्रतिनिधि कक्ष - राहुल गांधी के कक्ष - में आयोजित करने पर सहमति जताई। राहुल गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती अक्सर उनकी बिना सोचे-समझे दिए गए बयानों की प्रवृत्ति रही है। समर्थक उनकी सहज शैली की प्रशंसा करते हुए इसे प्रामाणिकता का प्रमाण मानते हैं, वहीं आलोचकों का तर्क है कि इसने विरोधियों को बार-बार उन्हें रक्षात्मक स्थिति में लाने का आसान अवसर प्रदान किया है। सबसे बड़ा विवाद 2019 में उनके 'मोदी उपनाम' वाले बयान से उत्पन्न हुआ, जिसके कारण अंततः उन्हें मानहानि के मुकदमे में दोषी ठहराया गया और संसद से अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में, उनके कई अन्य बयानों ने कानूनी शिकायतों और राजनीतिक विवादों को जन्म दिया है, जिससे वे अनावश्यक लड़ाइयों में उलझे रहे हैं। भाजपा राहुल गांधी की सहज टिप्पणियों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में विशेष रूप से सफल रही है। हिंदू समाज, जातिगत समीकरणों या संस्थाओं के भीतर सत्ता के केंद्रीकरण पर उनकी टिप्पणियों को अक्सर चुनिंदा रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि उन्हें विभाजनकारी या मुख्यधारा की सोच से कटा हुआ दिखाया जा सके। इसी तरह, विदेशों में दिए गए उनके भाषणों की विरोधियों द्वारा अक्सर इस रूप में आलोचना की जाती है कि वे विदेशी धरती पर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं।

इंडिया गठबंधन के 5 निर्णय से विपक्ष को मिली संजीवनी?

सौरभ वार्ष्णेय

अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनावों के बाद देश की राजनीति में विपक्षी दलों के गठबंधन (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) की बैठक में लिए गए पांच प्रमुख निर्णय केवल राजनीतिक घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की आगामी रणनीति का खाका भी प्रस्तुत करते हैं। इन निर्णयों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि विपक्ष चुनावी पारदर्शिता, शिक्षा, आर्थिक चुनौतियों और संसदीय समन्वय जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इस बैठक से कुछ हद तक क्षेत्रियों दलों को संजीवनी मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी प्रदेशों में इन समस्याओं को लेकर आंदोलनरत हैं। अच्छी बात यह ही कि आज भी इस विपक्षी खेमे में 23 दलों ने उपस्थिति दर्ज कराई।

1. मतदाता सूची और चुनावी निष्पक्षता का मुद्दा : बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मतदाता सूची में कथित हेरफेर, विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनावों की निष्पक्षता पर उठे प्रश्नों के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा जाएगा। यह निर्णय दर्शाता है कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाना चाहता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव उसकी आत्मा होते हैं। यदि मतदाता सूची या चुनावी प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न होता है तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सभी पक्ष तथ्यात्मक प्रमाणों और संवैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पर अपनी बात रखें। मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजने का निर्णय विपक्ष द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी चिंता व्यक्त करने का प्रयास माना जा सकता है।

2. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग: बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से जुड़ा है। हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, अनियमितताओं और प्रशासनिक विफलताओं के आरोप लगातार सामने आए हैं।लाखों युवाओं की मेहनत

और भविष्य इन परीक्षाओं से जुड़ा होता है। जब परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं तो केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे भर्ती तंत्र की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। विपक्ष इसी जनभावना को राजनीतिक मुद्दा बना रहा है।यद्यपि इस्तीफा मांगना विपक्ष का राजनीतिक अधिकार है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। देश के युवाओं को राजनीतिक बयानबाजी से अधिक भरोसेमंद व्यवस्था की आवश्यकता है।

3. आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और महंगाई पर सर्वदलीय बैठक की मांग : विपक्ष ने बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और आर्थिक चुनौतियों पर केंद्र सरकार से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक मुद्दे सीधे आम नागरिकों के जीवन से जुड़े हैं। रोजगार के अवसर, बढ़ती कीमतें, कृषि संकट और आय असमानता जैसे विषय केवल राजनीतिक बहस नहीं बल्कि जनजीवन की वास्तविक चुनौतियां हैं।सर्वदलीय बैठक की मांग यह संदेश देती है कि विपक्ष इन मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति और व्यापक चर्चा चाहता है। यदि सरकार इस दिशा में पहल करती है तो लोकतांत्रिक संवाद को मजबूती मिल सकती है। वहीं यदि यह मांग अनसुनी रहती है तो विपक्ष इसे जनआंदोलन का रूप देने का प्रयास कर सकता है।

4. प्रत्येक दो माह में बैठक का निर्णय: गठबंधन ने प्रत्येक दो माह में नियमित बैठक करने तथा अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में आयोजित करने का निर्णय लिया है।गठबंधन राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न दलों के बीच समन्वय बनाए रखना होती है। पिछले अनुभव बताते हैं कि कई विपक्षी गठबंधन आंतरिक मतभेदों के कारण कमजोर पड़ गए। ऐसे में नियमित बैठकों का निर्णय गठबंधन को सक्रिय और संगठित बनाए रखने का प्रयास है।हैदराबाद में अगली बैठक आयोजित करने का फैसला दक्षिण भारत को राजनीतिक रूप से अधिक महत्व देने की रणनीति का भी संकेत माना जा सकता है। इससे गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

5. मानसून सत्र में संसदीय समन्वय: बैठक का पांचवां निर्णय संसद के मानसून सत्र से जुड़ा है। सभी दलों ने प्रतिदिन समन्वय बैठक आयोजित करने और संसद के भीतर एकजुट रणनीति अपनाने पर सहमति व्यक्त की है।संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है। यदि विपक्ष समन्वित ढंग से कार्य करता है तो वह सरकार को अधिक प्रभावी ढंग से जवाबदेह बना सकता है। यह निर्णय संकेत देता है कि विपक्ष आगामी सत्र में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चुनावी पारदर्शिता और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा।

राजनीतिक मायने : इन पांच निर्णयों से तीन बड़े संदेश निकलकर सामने आते हैं— विपक्ष चुनावी पारदर्शिता को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है। युवा, रोजगार और शिक्षा जैसे जनसरोकारों को केंद्र में रखकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है।गठबंधन अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर 2029 की राजनीतिक चुनौतियों के लिए दीर्घकालिक तैयारी करना चाहता है। जनबंधन की बैठक के निर्णय विपक्ष की सक्रियता और एकजुटता का संकेत देते हैं। चुनावी पारदर्शिता, शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियां और संसदीय समन्वय जैसे मुद्दे लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब यह देखना होगा कि विपक्ष इन मुद्दों को जनआंदोलन का स्वरूप दे पाता है या नहीं, और सरकार इन मांगों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देती है। लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष उतना ही आवश्यक है जितनी एक मजबूत सरकार। इसलिए इन निर्णयों का महत्व केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श को दिशा देने के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जाएगा।

देवेगौड़ा ने आलेख लिख कर बताया मोदी की सफलता का राज

नीरज कुमार दुबे

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, कार्यशैली और राजनीतिक यात्रा पर अपने विचार रखते हुए कहा है कि मोदी की सबसे बड़ी विशेषता उनका आत्मचिंतनशील स्वभाव है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर लिखे गये अपने आलेख में देवेगौड़ा ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी केवल लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि वह ऐसे जननेता हैं जिन्होंने बदलते भारत की आकांक्षाओं, चुनौतियों और लोकतांत्रिक चेतना को समझते हुए स्वयं को समय के अनुरूप ढाला है।

देवेगौड़ा लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इस उपलब्धि ने जवाहरलाल नेहरू का पुराना कीर्तिमान पीछे छोड़ दिया है। यह केवल एक व्यक्ति की राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और जीवंतता का प्रमाण भी है।

अपने आलेख में वह बताते हैं कि जब नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, तब परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, महात्मा गांधी का नैतिक प्रभाव और कांग्रेस का व्यापक प्रभुत्व उनके साथ था। उस समय विपक्ष बेहद कमजोर था और चुनावी प्रतिस्पर्धा सीमित थी। 1952 के पहले आम चुनाव में केवल कुछ ही दल मैदान में थे और मतदाताओं की संख्या भी अपेक्षाकृत कम थी।

इसके विपरीत नरेंद्र मोदी ने ऐसे दौर में राजनीति की जब देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। अब लोकतंत्र अधिक जागरूक, प्रश्न पूछने वाला और प्रतिस्पर्धी हो गया है। मोदी ने वर्ष 2014 में पहली बार और फिर 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया। देवेगौड़ा के अनुसार यह उपलब्धि साधारण नहीं है, क्योंकि आज

का मतदाता अधिक सजग और अपेक्षाओं से भरा हुआ है।

अपने आलेख में देवेगौड़ा इस बात पर भी जोर देते हैं कि पहले के प्रधानमंत्रियों को जो सामाजिक और राजनीतिक आधार सहज रूप से मिल जाता था, वह मोदी जैसे नेताओं को नहीं मिला। न तो वह किसी राजनीतिक वंश से आए और न ही उनके पास कोई पारिवारिक विरासत थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, संगठन क्षमता और जनता से सीधे संवाद के बल पर स्वयं को स्थापित किया।

देवेगौड़ा अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनका स्वयं का प्रधानमंत्री कार्यकाल बहुत छोटा रहा, इसलिए वह यह देखकर आश्चर्य करते हैं कि नरेंद्र मोदी लगातार लंबे समय तक जनता का विश्वास बनाए रखने में कैसे सफल रहे? उनके अनुसार इसका उत्तर मोदी की अद्भुत ऊर्जा, अनुशासन और निरंतर आत्ममंथन में छिपा है।

देवेगौड़ा के आलेख में नेहरू और मोदी के समय के बीच सामाजिक बदलावों की तुलना भी की गई है। देवेगौड़ा लिखते हैं कि नेहरू के समय मंत्रिमंडल में समाज के विभिन्न वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। उस दौर में ऊंची जातियों का वर्चस्व अधिक दिखाई देता था। इसके विपरीत मोदी के मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की भागीदारी अधिक दिखाई देती है। इसे वह आधुनिक भारत की सामाजिक विविधता का प्रतिबिंब मानते हैं।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी देवेगौड़ा ने मोदी सरकार की सराहना की है। उनका कहना है कि संसद और राजनीति में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में जो प्रयास हुए हैं, वह भारत को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

देवेगौड़ा के अनुसार आज का भारत नेहरू काल के भारत से बहुत अलग है। अब नागरिक अधिक शिक्षित, जागरूक और अधिकारों के प्रति सजग हैं। सामाजिक न्याय, पर्यावरण, महिला अधिकार और नागरिक अधिकार जैसे विषयों पर समाज में गहरी चर्चा होती है। ऐसे समय में शासन चलाना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो गया है।

अपने आलेख में देवेगौड़ा ने मोदी की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि का भी उल्लेख किया। उन्होंने लिखा है कि मोदी ने भारत को तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। साथ ही राष्ट्रीय हितों की रक्षा के मामले में उन्होंने दृढ़ता दिखाई है। उन्होंने लिखा है कि सैन्य संघर्षों और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के समय उनका निर्णयात्मक नेतृत्व स्पष्ट रूप से सामने आया। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा यह भी कहते हैं कि मोदी केवल प्रशासनिक प्रमुख नहीं हैं, बल्कि वह जनता से भावनात्मक जुड़ाव रखने वाले नेता हैं। अपने रेडियो संवाद, तकनीक के उपयोग और सीधे संपर्क के माध्यम से उन्होंने समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया है।

अपने आलेख के अंत में देवेगौड़ा निष्कर्ष देते हैं कि नरेंद्र मोदी की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका आत्मचिंतनशील स्वभाव है। वह निरंतर स्वयं का मूल्यांकन करते रहते हैं, जनता की अपेक्षाओं को समझते हैं और बदलते समय के अनुसार अपने कार्य और दृष्टिकोण में सुधार करते रहते हैं। यही गुण उन्हें लंबे समय तक जनविश्वास प्राप्त कराने में सबसे अधिक सहायक बना है।

तृणमूल कांग्रेस के बागियों पर दलबदल विरोधी कानून भी बेअसर

राकेश कुमार

सत्ता से बाहर होने के बमुश्किल एक महीने बाद ही राज्य विधानसभा में सामने आई बगावत से जूझ रही तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का संकट अब संसद तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। यह स्थिति विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए भी एक चुनौती है। हालिया चुनाव में करारी शिकस्त और विधानसभा में बगावत के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों के संसद तक पहुंचने से साफ है कि पार्टी अपने इतिहास के सबसे गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। राजनीतिक दल आमतौर पर चुनावी हार के बावजूद बने रहते हैं, लेकिन वर्षों से जमी सत्ता के एकाएक छिन जाने से अक्सर उन्हें टिके रहने में मुश्किल होती है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ यही हो रहा है। सत्ता से बाहर होने के बमुश्किल एक महीने बाद ही उसे अपने ज्यादातर विधायकों व सांसदों की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। ममता के लिए यह एक बड़ा झटका इसलिए भी है, क्योंकि बागी समूह का आकार संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे आमतौर पर दलबदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, के तहत अयोग्यता से सुरक्षा के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े को पार करता दिख रहा है। लिहाजा तृणमूल कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ खोई हुई चुनावी जमीन पाने तक सीमित नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी परीक्षा अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखने की है। इसमें संदेह नहीं कि ममता बनर्जी ने अपने संघर्ष के बल पर तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया और पश्चिम बंगाल की राजनीति में वामपंथी प्रभुत्व का अंत किया। लेकिन, राजनीतिक इतिहास यह भी बताता है कि किसी भी दल का भविष्य केवल करिश्माई नेतृत्व पर निर्भर नहीं रह सकता। समय के साथ संगठनात्मक

संस्थाओं को मजबूत करना, दूसरी पंक्ति के नेतृत्व को तैयार करना और असहमति को समायोजित करने की क्षमता विकसित करना भी उतना ही जरूरी होता है। तृणमूल कांग्रेस का संकट पहले से ही नेतृत्व, रणनीति और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के सवालों से जूझ रहे इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इससे न केवल संसद के भीतर विपक्ष की संख्या और प्रभाव घट सकता है, बल्कि भाजपा के मुकाबले एक व्यापक और विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करने की उसकी क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। दिलचस्प यह है कि जिस कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ था, अब उसी की ओर से ममता बनर्जी को कथित तौर पर घर वापसी का प्रस्ताव दिया गया है। दरअसल, कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक वोट वाम दलों और तृणमूल के बिखरे धड़ों में बंट जाएं। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में कभी परिवर्तन का प्रतीक बनकर उभरी तृणमूल कांग्रेस का मौजूदा संकट केवल उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता का नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व और विपक्षी राजनीति में उसकी भावी भूमिका का भी है। आने वाले दिनों में पार्टी इस चुनौती का सामना कैसे करती है, यही उसके भविष्य की दिशा तय करेगा।

हड्डियां व दांत बनाए मजबूत

दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद आवश्यक होता है। सिर्फ बढ़ते बच्चों के लिए ही कैल्शियम जरूरी नहीं होता, बल्कि वयस्कों को भी अपनी हड्डियां मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। इससे वे ऑस्टियोपोरोसिस से बचे रहते हैं। दूध दांतों के लिए भी फायदेमंद होता है। यह दांतों की सड़न और कैविटी से बचाए रखने में मदद करता है।

डेस्क जॉब करने वाले जरुर करें ये काम

डेस्क जॉब करने वालों को कई सारी बीमारियां एक साथ लगती हैं। अगर आप घंटो अपनी कुर्सी से चिपके रहेंगे तो आपको दिल की बीमारी, मोटापा, पीठ दर्द, स्लिप डिस्क या अन्य बीमारी होने का खतरा हो सकता है। अगर आप अपने दिन का 8-9 घंटा ऑफिस में ही काटते हैं तो आप ऑफिस में ही कुछ कुछ देर पर उठ कर टहल लें या सीट पर बैठ कर ही स्ट्रेचिंग कर लें तो भी आपको काफी लाभ मिलेगा।

रोज खाना चाहिए केला?

जब आपको टाइप-2 डायबिटीज होता है तो आपका शरीर उचित मात्रा में इन्सुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता जिसके कारण रक्त में से ग्लूकोज खींच लिया जाता है ताकि कोशिकाओं में उसे एकत्रित करके रखा जा सके। इसके परिणामस्वरूप आपके शरीर में शुगर (शर्करा) का स्तर बढ़ता या घटता रहता है। इसका अर्थ यह है कि आपके शरीर में शुगर के स्तर को नियमित करने में आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिक ग्लाइसिमिक युक्त आहार लेने से शुगर का स्तर एकदम बढ़ जाता है तथा शुगर के तुरंत बर्न होने के बाद अचानक कम हो जाता है।

केले में क्या होता है?

केला फाइबर का समृद्ध स्त्रोत होने के अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन बी6 और पौटेशियम भी मौजूद रहता है जिसके कारण इसे आहार में शामिल करना अच्छा माना जाता है। जहां बी6 आपके मूड को अच्छा रखता है वहीं विटामिन सी आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, पौटेशियम आपके ब्लडप्रेशर को नियमित रखता है तथा फाइबर के कारण आपको पेट काफी समय तक भरा हुआ महसूस होता है। एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि केले में उपस्थित स्टार्च (24 ग्राम प्रतिदिन) इन्सुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ने में सहायक होता है तथा टाइप-2 डायबिटीज में वजन कम करने में सहायक होता है। डायबिटीज के रोगियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि केले में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं तथा आपके आहार में इसे शामिल करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।

डायबिटीज रोगी खा सकते हैं केले

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने डायबिटिक लोगों को (डायबिटीज के मरीजों को) केला खाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनके अनुसार केला एक स्वस्थ आहार है जिसका सेवन करना पूर्णतया उचित है। वास्तव में एक अध्ययन से पता चला है कि यदि आप टाइप-2 के डायबिटीज को दूर करना चाहते हैं तो केला सबसे उत्तम फल है।

कच्चे केले या पके हुए केले

जैसे जैसे केला पकता है उसमें उपस्थित स्टार्च, शुगर (शर्करा) में बदलने लगता है। जब आप पूर्ण रूप से पका हुआ केला खाते हैं तो आप ऐसे फल का सेवन करते हैं जिसमें लगभग 90 प्रतिशत स्टार्च होता है। यही कारण है कि शोधकर्ता कहते हैं कि कच्चा केला कम ग्लायसिमिक प्रतिक्रिया देता है। अतः पके हुए केले की तुलना में कच्चा केला अधिक श्रेष्ठ है।

प्रतिदिन कितने केले खाएं?

आप प्रतिदिन एक केले का सेवन कर सकते हैं। आपको अपने आहार की मात्रा पर ध्यान देना आवश्यक है। जब केले की बात आती है तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन आपको यह बताना चाहता है कि कितनी मात्रा का सेवन किया जा सकता है। उनके अनुमानों के अनुसार केले के आकार के अनुसार उसके कार्बोहाइड्रेट घटक में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए एक बहुत छोटे केले (लगभग 6 इंच या उससे कम) में केवल 18.5 ग्राम कार्ब्स होता है। दूसरी ओर मध्यम आकार के (लगभग 7 से 7 7/8 इंच) केले में 27 ग्राम कार्ब्स होता है। 9 इंच या उससे अधिक ब? केले में 35 ग्राम से अधिक कार्ब्स होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की ग्लूकोज के प्रति प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, अतः आपके शरीर के लिए क्या सही है यह जानने के लिए आपको अपने विवेक का उपयोग करना होगा। अपने आहार की मात्रा में फल सब्जियों और केले के बीच संतुलन बनाएं। क्योंकि आहार के मामले में संयम रखना बहुत आवश्यक है और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाना बहुत अच्छी बात है। तो यदि आप अपने आहार में सेब, अंगूर, ब्लूबेरीज को शामिल कर सकते हैं तो आप अपने शरीर में शुगर के स्तर को आसानी से संतुलित रख सकते हैं।

इसके अलावा शरीर में शुगर के स्तर एक जैसा रखने के लिए फल तथा कार्ब्स का सेवन दिन में थोड़े-थोड़े अंतराल पर करें। सही तरीके से अपनी योजना बनाएं तथा दिन में एक केले के सेवन का आनंद उठायें। इस प्रकार डायबिटीज के रोगी केला खाने से होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं।

जिम के बाद पावरफुल बनाएंगी ये सुपर ड्रिंक्स

घर पर बने पेय पदार्थ, हेल्दी और सस्ते होते हैं जबकि मार्केट में पैकेट में बिकने वाले पेय पदार्थ में प्रीर्जवेटिव मिला होता है और इनमें सुगर की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। ऐसे में अगर इनका सेवन जिम के तुरंत बाद किया जाए तो लाभ की बजाय नुकसान ही करेंगे और आपके द्वारा जितनी कैलोरी वहां कम की गई है उतनी कैलोरी आप आते ही ग्रहण कर लेंगे।

साथ ही इनमें सिंथेटिक एडीटिव्स, कलर्स और असामान्य फ्लेवर पड़े हुए होते हैं जो नुकसान करते हैं। इसलिए, अपने दिन की शुरूआत नीचे बताए जाने वाले पेय पदार्थों का सेवन करके करें।

इन पेय पदार्थों को सुबह ट्राई करें और जिम से आने के बाद खासतौर पर पिएं। इसस आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी और फैट भी नहीं बढ़ेगा। फलों के रस से बनने वाले ये पेय पदार्थ आपको तंदुरूस्त बनाने में मददगार साबित होंगे। आइए जानते हैं इन चार सुपर ड्रिंक्स के बारे में

चॉकलेट ड्रिंक

चॉकलेट में प्राकृतिक रूप से कैफीन पड़ा हुआ होता है, इसीलिए इससे आने वाली महक आपको इसे पीने के लिए मजबूर कर देती है। इस ड्रिंक में सुगर मिलाने की जरूरत नहीं होती है इसमें फलों की सुगर ही बनी रहती है। इसकी ठंडक भरी महक आपको तरोताजा कर देगी।

व्हीटग्रास और बनाना ड्रिंक

व्हीटग्रास को कई सालों से स्वास्थ्यवर्धक ड्रिंक माना जाता है क्योंकि इससे शरीर को बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर इसे पके हुए केले के साथ फेंट लें और तब पिएं तो यह ज्यादा लाभ देगा। गुणों से भरा गेहूं के जवारे का पाउडर

गाजर और संतरे का ड्रिंक

अगर आप अपनी सुबह ऊर्जावान बनाना चाहते हैं तो गाजर और संतरे का जूस निकाल कर पिएं। इस पेय पदार्थ में विटामिन सी, ई की भरमार होगी। इससे आपको पूरे दिन शक्ति महसूस होगी। साथ ही आपको थकान भी नहीं होगी।

मेपल सिरप पिएं

मेपल सिरप पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और आपके शरीर में सुगर की मात्रा भी नहीं बढ़ती है। इस पेय पदार्थ में सोडियम भी होता है

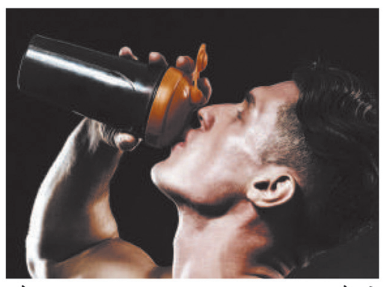

और अगर आपका रक्तचाप ज्यादा रहता है तो इसे न पिएं।

ये पेय पदार्थ न सिर्फ आपके शरीर को ताकत देते हैं बल्कि डिटॉक्सीफिकेशन की प्रक्रिया में भी सहायक होते हैं। अगर आपको इन ड्रिंक्स का स्वाद थोड़ा कम अच्छा लगे तो इसमें अदरक को भी मिलाया जा सकता है। इन्हें पीकर आप सारा एनर्जीफुल फील कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। बस इन ड्रिंक्स को एक कप पीने मात्र से शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है।

त्वचा पर स्ट्रॉबेरी और दही लगाने के फायदे

स्ट्रॉबेरी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक फल है तथा दही एक प्राकृतिक घटक है जो स्वास्थ्य पर आश्चर्यजनक परिणाम दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी तथा दही दोनों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपकी त्वचा की रंगत को प्राकृतिक तरीके से निखारते हैं? जब इन दोनों घटकों को आपस में मिलाया जाता है तो त्वचा को मिलने वाले फायदे भी दोगुने हो जाते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि कुछ ताजा कटी हुई स्ट्रॉबेरीज लें तथा इन्हें ब्लेंडर में पीसकर पेस्ट बनाएं। अब स्ट्रॉबेरी के इस पेस्ट में 2 टेबलस्पून दही मिलाएं। दोनों को अच्छे से मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। स्ट्रॉबेरी और दही के इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं। इसे 20 मिनिट लगा रहने दें तथा बाद में फेस वॉश से चेहरा धो डालें। स्ट्रॉबेरी और दही के मिश्रण से बने फेस पैक से होने वाले अन्य लाभों के बारे में जानें।

एंटी ऐजिंग प्रभावः स्ट्रॉबेरी और दही के मिश्रण में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो आपकी त्वचा की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है तथा कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है जिससे झुर्रियां तथा फाइन लाइंस दूर होती है।

मधुमेह में फायदेमंद है अमरूद का सेवन

मधुमेह ऐसी बीमारी है जो एक बार होने पर जीवनभर साथ निभाती है। मधुमेह पर नियंत्रण के लिए खानपान पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मधुमेह रोगियों को ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जिससे उनका ब्लड ग्लूकोज का स्तर न बढ़े।

मधुमेह रोगियों को अमरूद खाने की सलाह दी जाती है। अमरूद में प्रोटीन 10.5 प्रतिशत, वसा 0.2 कैल्शियम 1.01 प्रतिशत बी 0.2 प्रतिशत पाया जाता है। ये फल मीठा होते हुए भी मधुमेह को नियंत्रित रखता है। मधुमेह के रोगियों को इस फल का सेवन करना चाहिए। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं।

कैसे करें अमरूद का सेवन

हर सीजन में मिलने वाला अमरूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। खासकर मधुमेह के रोगियों के लिए यह वरदान की तरह है। इसको कई तरह से खाया जा सकता है। डायबिटीज के रोगी के लिए एक पके हुए अमरूद को आग में डालकर उसे भूनकर निकाल लें और भुने हुई अमरुद को छीलकर साफ करके उसे अच्छे से मैश करके उसका भरता बना लें, उसमें स्वादानुसार नमक, कालीमिर्च, जीरा मिलाकर खाएं, इससे डायबिटीज में काफी लाभ होता है।

ताजे अमरूद के 100 ग्राम बीजरहित टुकड़े लेकर उसे ठंडे पानी में 4 घंटे भीगने दीजिए। इसके बाद अमरूद के टुकड़े निकालकर फेंक दें। इस पानी को मधुमेह के रोगी को पिलाने से लाभ होता है।अमरूद तो फायदेमंद होता ही हैं लेकिन इसका जूस भी गुणकारी होता हैं। घर पर बनाए गए जूस में स्वाद और गुण दोनों ही बरकरार रहते हैं । जूस में मिनरल्स और न्यूट्रीएंट्स की मात्रा अधिक होती हैं ।

अमरूद पोषक तत्वों की खान है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में दो अमरूद से ज्यादा खाने से बचना चाहिए। पचने में दिक्कत होने के कारण अगर हो सके तो इसके बीज निकाल कर खाएं। इससे पेट दर्द की आशंका नहीं रहती।

अमरूद में विटामिन ए और विटामिन सी के अलावा फाइबर भी होता है। अमरूद पत्ती से बनी चाय में एल्फा-ग्लूकोसाइडिस एंजाइम गतिविधि को कम कर मधुमेह रोगियों में प्रभावी रूप से रक्त शर्करा को कम करती है। इसके अलावा यह सुक्रोज और माल्टोज को सोखने से शरीर को रोकती है जिससे शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। अमरूद की पत्ती से बनी चाय 12 सप्ताह पीने से इंसुलिन के उत्पादन में वृद्धि के बिना रक्त में शर्करा के स्तर को कम कर सकते हैं। फाइबर से धनी अमरूद शरीर में मीठे की खपत को धीमा करता है। नियमित सेवन टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को कम करने में मदद करता है। अमरूद का प्रभाव अग्नाशय पर भी अच्छा असर डालता है जिस कारण मधुमेह के रोगियों के लिए पके अमरूद का नियमित सेवन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है।

मधुमेह को नियंत्रित करता है अमरूद

चॉकलेट देती है तनाव और थकान से तुरंत राहत

जो लोग मुंह मीठा करने के लिए चॉकलेट खाते हैं, उन्हें यह जान कर हैरत होगी कि चॉकलेट का प्रारंभिक नाम बिटर वॉटर यानी कड़वा पानी रखा गया था। दक्षिण अमेरिका में थियोब्रोमा कोकोआ पेड़ से चॉकलेट उत्पादन किया जाता था। चॉकलेट का प्रारंभिक उल्लेख 1100 बीसी में देखने को मिलता है।

उस वक्त चॉकलेट एजटेक्ट बेवरेज को शाही बनाने के लिए चॉकलेट का इस्तेमाल प्रमुख रूप से किया जाता है। कोकोआ पेड़ का बीज मूलतः कड़वा होता है, जिसमें खमीर उठाया जाता है, सुखाया जाता है और फिर उसे भूना जाता है। कोकोआ पाने के लिए उसकी परत को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया तक चॉकलेट कच्चे माल के रूप में होती है।

जिसे आज हम चॉकलेट कहते हैं, वह मीठी होती है, जिसमें कोकोआ सॉलिड, बटर और अन्य वसा व चीनी मिलाई जाती है। चॉकलेट का इस्तेमाल कई तरह के पेय पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। खासतौर पर बेवरेजेस में, जिसमें मेक्सिको शराब भी शामिल है। फल व मेवा के साथ मिलाकर चॉकलेट को सीधे ही खाया भी जाता है। केक और डेजर्ट में भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। जहां चॉकलेट की शुरुआत हुई, उस सेंटर अमेरिका में चॉकलेट का इस्तेमाल चिकन और मीट में भी किया जाता है।

रेसिपी

ब्लॅक बीन डिप

सामग्री

1/2 कप ब्लॅक बीन्स , रातभर भिगोए और छाने हुए, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 कप बारीक कटे हुए टमाटर, 2 टी-स्पून नींबू का रस, 1 टेबल-स्पून सूखी लाल मिर्च के फ्लैक्स, 1 टी-स्पून सूखे मिले-जुले हर्बस, नमक स्वादअनुसार, **परोसने के लिए:** नाचो चिप्स

विधि

ब्लॅक बीन्स, नमक और 21/2 कप पानी को एक प्रैशर कुकर में अच्छी तरह मिला लें और 5 सिटी तक प्रैशर कुक कर लें। ढक्कन खोलने से पुर्व सारी भाप निकलने दें। अच्छी तरह छानकर, ब्लॅक बीन्स् को एक गहरे बाउल मे निकाल लें। बची हुई सभी सामग्री डालकर, आलू मैशर का प्रयोग कर दरदरे मिश्रण में मसल लें। कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज मे रखकर, चिप्स् के साथ ठंडा परोसें।

चीज़ी नूडल कटलेट

सामग्री

1/2 कप कसा हुआ प्रोसेस्ड चीज, 1 कप उबले हुए नूडल्स, 1/2 कप उबले और क्रश किए हुए मीठी मकई के दानें, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरी प्याज का सफेद भाग, 1/4 कप बारीक कटे हुए हरी प्याज़ के पत्ते, 2 टी-स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक और ताज़ी पिसी काली मिर्च , स्वादअनुसार, **रोल करने के लिए:** ब्रेड क्रम्बस, **तलने के लिए:** तेल, **परोसने के लिए:** टमेटो कैचप

विधि

सभी सामग्री को एक गहरे बाउल में अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को 6 बराबर भाग में बांटकर, प्रत्येक भाग के 75 मिमी (3) आकार के चपटे, गोल कटलेट बना लें। प्रत्येक कटलेट को ब्रेड क्रम्बस् में अच्छी तरह से सभी तरफ से लपेट लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें और थोड़े-थोड़े कटलेट डालकर, उनके सभी तरफ से सुनहरा होने तक तल लें। तेल सोखने वाले कागज़ पर निकाल लें। टमेटो कैचप के साथ तुरंत परोसें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने की विशिष्ट उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर उनके नेतृत्व में जनता द्वारा जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, आपका कार्यकाल शासन, आर्थिक मजबूती और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी उपलब्धियों से चिह्नित रहा है।'' मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के लगातार कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मुर्मू ने कहा, ''राष्ट्र के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने के इस अद्वितीय सम्मान पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक बधाई।

पीएम मोदी ने बिना छुट्टी लिए देश की सेवा की : रेखा गुप्ता

नईदिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेन्द्र मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर बुधवार को उत्तरी दिल्ली की किशनगंज गौशाला का दौरा किया और एक मंदिर में पूजा-अर्चना की। गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा कि आज वह (मोदी) सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं और वह बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए, देश की सेवा कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि करोड़ों लोग प्रधानमंत्री के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर कोई देश का सम्मान बढ़ाने और विकसित भारत के उनके दृष्टिकोण के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता है, जिसके लिए वह निरंतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं के केंद्र में महिलाएं हैं, चाहे वह देशभर में शौचालयों को बढ़ावा देकर उन्हें सम्मान देना हो या उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराकर उनके जीवन को आसान बनाना हो।

नटराजन मामले में चुनाव आयोग से मिले कांग्रेस नेता

भोपाल। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द किए जाने के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बुधवार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को गलत, पक्षपातपूर्ण और कानून के विरुद्ध बताते हुए उसे तत्काल निरस्त करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जयराम रमेश, दीपा दासमुंशी, विवेक तन्खा, अभिषेक मनु सिंघवी और स्वयं मीनाक्षी नटराजन शामिल थीं। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के समक्ष तर्क रखा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। पार्टी का कहना है कि उनके खिलाफ दायर निजी शिकायत पर अभी तक किसी अदालत ने संज्ञान नहीं लिया है।

टीएमसी की सुष्मिता देव ने सांसद पद से दिया इस्तीफा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर मची अंदरूनी कलह और बगावत अब दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी पर पकड़ लगातार कमजोर होती दिख रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बागी नेता रितब्रता बनर्जी के समर्थन में 61 विधायकों के लामबंद होने के बाद, अब यह असंतोष संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) में भी फूट पड़ा है। पार्टी के बेहद भरोसेमंद और वरिष्ठ सहयोगी सुखेंदु शेखर रॉय के राज्यसभा से इस्तीफा देने के ठीक एक हफ्ते बाद, बुधवार को टीएमसी की तेजतर्रार नेता सुष्मिता देव ने भी उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक ही हफ्ते के भीतर दो बड़े राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे ने ममता बनर्जी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। सुष्मिता देव देश की राजनीति, विशेषकर उत्तर-पूर्व का एक जाना-माना चेहरा हैं।

राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच हुई अहम बैठक

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। यह बैठक 10 जनपथ पर हुई। विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच तालमेल बढ़ाने और एकता बनाए रखने की कोशिशों के तहत यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। यह बैठक ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात के ठीक एक दिन बाद हुई है। मंगलवार को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी के आवास पर जाकर उनसे बात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने विपक्षी गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करने के रास्तों पर चर्चा की थी। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की यह मुलाकात इस हफ्ते दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक का ही हिस्सा है। उस बैठक में विपक्षी दलों ने भाजपा का मुकाबला करने के लिए आपसी सहयोग और एकता की जरूरत बताई थी। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं ने बगावती तेवर दिखाए हैं।

12 सालों में देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ : पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे इतने लंबे समय तक सेवा करने का सौभाग्य मिला। आज का दिन आप सभी ने मेरे लिए बहुत यादगार बना दिया है। मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति-चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार-चढ़ाव देखते हुए, एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था।

निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने का अवसर, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। आपने इस अवसर पर मुझे सम्मानित किया, इतना मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूं।

जनता-जनार्दन का किया आभार व्यक्त

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को नमन करता हूं, जनता-जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।

कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ

एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था।

देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे-धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है और बड़ी ही चतुराई से धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट।

इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में न सुशासन था, न नीति, न नीयत और ना निर्णय। पहली बार अटल जी के नेतृत्व में छह सरकार आई तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ों रुपये के घोटालों में घसीट दिया।

देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नीयत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है।

देश में एक नई आशा का उदय हुआ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साल 2014 में जब छह की जीत हुई थी तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद जिस अपने भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि छह परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है।

अमित शाह ने गिनाईं पीएम मोदी के 12 साल की उपलब्धियों को

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने उन्हें बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट में, अमित शाह ने प्रधानमंत्री को दिल से बधाई दी और पिछले 12 सालों को भारत के आत्म-सम्मान को मजबूत करने, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और देश को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने के निरंतर प्रयासों का दौर बताया। प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर बात करते हुए, शाह ने कई अहम उपलब्धियों का जिक्र किया, जिनमें नए संसद भवन का निर्माण, तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत और आत्मनिर्भर भारत के विजन को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने कहा कि यह विजन देश भर के नागरिकों द्वारा अपनाया गया एक राष्ट्रीय संकल्प बन गया है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले 12 सालों में कई बड़े बदलाव हुए, जिनमें जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शामिल है। शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और भारत की विरासत, संस्कृति और क्षमताओं के प्रति गर्व की नई भावना जगाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया, साथ ही देश को वैश्विक मंच पर एक आत्मविश्वास से भरी और प्रभावशाली आवाज के रूप में स्थापित करने में मदद की।

एक्स पर उनके पोस्ट में लिखा है, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व के ये 12 साल भारत के आत्म-सम्मान को मजबूत करने, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और देश को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने के प्रयासों के लिए जाने जाएंगे।

शाह ने कहा, इस दौरान संसद की नई इमारत बनी, तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और भारतीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का रास्ता खुला। आत्मनिर्भर भारत का विजन हर भारतीय का संकल्प बन गया।

शाह ने आगे कहा, इन 12 सालों में देश की सीमाएं मजबूत हुईं, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, राम मंदिर बना, नक्सलवाद पर लगाम लगी और आतंकवाद का कड़ाई से मुकाबला किया गया। साथ ही, देश की सामूहिक ताकत ने लोगों को हीन भावना से बाहर निकलने और भारत की विरासत, संस्कृति और क्षमताओं पर गर्व करने में मदद की।

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके आत्म-सम्मान व राष्ट्रीय गौरव की भावना को बहाल करना मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आज एक नया भारत हर वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान बना रहा है और दुनिया एक सक्षम, सशक्त और नए जोश के साथ भारत के उदय को देख रही है।

बता दें कि पीएम मोदी ने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिनों तक पद पर रहने का पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तुलना के लिए नेहरू के 1952 से शुरू हुए कार्यकाल को आधार माना गया है, क्योंकि देश में पहले आम चुनाव होने से पहले, 1947 से 1952 के बीच वे अंतरिम सरकार के प्रमुख थे।

एनडीए नेताओं ने दी बधाई, भारत मंडपम में झालमुड़ी का आनंद लिया

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नेताओं की एक बैठक को संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले इस गठबंधन को सत्ता में 12 साल पूरे हो रहे हैं। इस बैठक में एनडीए -शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, जो कामकाज और गठबंधन के भविष्य के रोडमैप पर चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले आज, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी के विजन का समर्थन करते हुए और राष्ट्रीय सुरक्षा, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय पर उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि वे भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं।मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पारित इस प्रस्ताव में उन्हें चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ने पर बधाई दी गई और भरोसा जताया गया कि उनके नेतृत्व में भारत एक आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र के रूप में नई ऊंचाइयां हासिल करता रहेगा। य लोक दल (आरएलडी), राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-अठावले (आरपीआई-ए), और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) भाग ले रहे हैं।

खेल

प्रमुख समाचार

हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान सीरीज से बाहर

मुंबई। भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या खेलने की स्वीकृति मिलने के कुछ घंटे बाद बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैच की एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए जब उनकी जांच की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। पंड्या बेंगलुरु में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में अपनी पीठ की ऐंठन की चोट से उबरने के बाद खेलने की मंजूरी लेने गए थे।

यह चोट उन्हें आईपीएल में मुंबई इंडियन्स के लिए खेलते समय लगी थी। हो सकता है कि यह नई चोट सीओई में आकलन के दौरान पूरे 10 ओवर की गेंदबाजी करने की वजह से लगी हो। अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला शनिवार को धर्मशाला में शुरू होगी। इसके बाद लखनऊ और चेन्नई में क्रमश: 17 और 20 जून को दो अन्य मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, ''उन्हें ठीक होने में तीन हफ्ते लगेंगे इसलिए उनके एकदिवसीय श्रृंखला में खेलने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि उनका रिहैबिलिटेशन पूरा नहीं हो पाएगा।''

पंड्या आईपीएल में मुंबई इंडियन्स के लिए कुछ मैच नहीं खेल पाए थे लेकिन 24 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम के आखिरी मैच में वापसी की थी। इस 32 साल के ऑलराउंडर को यह नई चोट ऐसे समय में लगी है जब अगले साल होने वाले एकदिवसीय विश्व कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक एकदिवसीय क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एकदिवसीय विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ पहले दौर के मैच के दौरान पंड्या के बाएं टखने में लगी चोट ने टीम का संतुलन बिगाड़ दिया था। दक्षिण अफ्रीका में 2027 में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप के लिए भारत की योजनाओं में पंड्या अहम बने हुए हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 630 अंक नीचे निफ्टी 23,215 पर बंद

नईदिल्ली। आज के कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार ने शुरुआती बढ़त गंवा दी। मेटल, पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर में बिकवाली के दबाव के चलते प्रमुख सूचकांक अपने दिन के उच्च स्तर से नीचे आ गए। निफ्टी 50 अंत में 27.15 अंक यानी 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,214.95 पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 64.42 अंक यानी 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,983.18 पर स्थिर हुआ। निफ्टी 50 के प्रमुख लूजर्स में हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन सबसे आगे रहे। इन दिग्गज शेयरों में कमजोरी का सीधा असर पूरे बाजार पर देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट में भी दबाव साफ नजर आया। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1.49 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 1.33 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ।

भारत बना ग्लोबल इकॉनमी का 'ब्राइट स्पॉट': चंद्रशेखरन

नईदिल्ली। एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत आज भी एक ब्राइट स्पॉट यानी उज्ज्वल अवसर वाला देश बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ तेज आर्थिक वृद्धि दे रहा है, बल्कि यहां एक बड़ा और मजबूत उपभोक्ता बाजार भी मौजूद है। वे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की 63वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित कर रहे थे।चंद्रशेखरन ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। भू-राजनीतिक बदलाव, सप्लाई चेन में रुकावटें, ऊर्जा परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से हो रही प्रगति वैश्विक अर्थव्यवस्था को नए सिरे से आकार दे रही है। उन्होंने यह भी बताया कि साल की शुरुआत भले ही सकारात्मक माहौल में हुई थी, लेकिन कई बड़े विकासों ने उम्मीदें बढ़ाई थीं।

मेटा भारत में बनाएगी अपना पहला एआई डेटा सेंटर

नईदिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की रेस में भारत की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सएप की मालिक मेटा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एक बड़ा समझौता किया है। दोनों कंपनियां मिलकर गुजरात के जामनगर में मेटा का भारत का पहला एआई डेटा सेंटर बनाएंगी। यह डेटा सेंटर 168 मेगावॉट क्षमता का होगा और मेटा इसे लीज पर लेकर इस्तेमाल करेगी। साथ ही कंपनी इसके संचालन के लिए जरूरी बिजली और पानी का पूरा खर्च भी खुद उठाएगी। दुनियाभर में एआई को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है और बड़ी टेक कंपनियां अपने डेटा सेंटर नेटवर्क को मजबूत करने में जुटी हैं। मेटा भी इसी दिशा में तेजी से निवेश कर रही है। कंपनी का कहना है कि जामनगर में बनने वाला यह डेटा सेंटर उसके एआई मॉडल्स और डिजिटल सेवाओं को और मजबूत बनाने में मदद करेगा।

आरबीआई के कदम के बाद बैंकों में ब्याज बढ़ाने की होड़

नईदिल्ली। विदेश में रहने वाले भारतीयों (एनआरआई) से ज्यादा पैसा आकर्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नई पहल का असर दिखने लगा है। देश के कई बैंकों ने विदेशी मुद्रा गैर-निवासी (बैंक) यानी एफसीएनआर(बी) जमा पर ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। एचडीएफसी बैंक ने बुधवार को एफसीएनआर(बी) जमा पर ब्याज दरों में 2.6 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की। इसके बाद बैंक अब 3 से 5 साल की अवधि वाले एफसीएनआर(बी) जमा पर अधिकतम 6 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। एचडीएफसी बैंक के अलावा यस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ये बैंक 3 से 5 साल की अवधि वाली एफसीएनआर(बी) जमा पर 7.10 प्रतिशत तक ब्याज ऑफर कर रहे हैं।

पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण की उलझी पहेली

अजय त्यागी

कितने लोगों को याद है कि सरकार ने वर्ष 2002 में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र (एपीएम) खत्म कर दिया था और उसी वर्ष 1 अप्रैल से पेट्रोल एवं डीजल के लिए बाजार आधारित मूल्य निर्धारण का ऐलान किया था?

तब से दो दशक गुजर जाने के बाद भी सरकार यह निर्णय लागू करने में सक्षम नहीं है जो इससे जुड़ी जटिलताओं का संकेत समझा जा सकता है। अफसोस की बात है कि उस विषय पर सिर्फ वर्तमान हालात जैसे समय में ही गंभीर जिक्र होता है। इस बात को सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण राजनीतिक रूप से एक संवेदनशील विषय है, मगर अब समय आ गया है कि सरकार इस संबंध में कड़े कदम उठाए, कठोर निर्णय ले और उन पर कायम रहे।

सबसे पहले कुछ तथ्यों पर विचार कर लेते हैं। ऊर्जा समूह (बास्केट) में तेल एवं गैस का अनुपात पिछले दो दशकों में लगभग स्थिर रहा है। यह वर्ष 2000 में लगभग 32 फीसदी था जबकि अब 31 फीसदी है। नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ते जोर, संरक्षण के विभिन्न प्रयासों और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने की योजनाओं के बावजूद तेल एवं गैस की घरेलू खपत में त्वरित कमी आने की गुंजाइश नहीं दिख रही है।

समय के साथ तेल और गैस आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान में यह घरेलू खपत का क्रमश: लगभग 85 फीसदी और 50 फीसदी है। भारत का कच्चा तेल आयात कुल वैश्विक तेल आयात का लगभग 12 फीसदी है और भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य निर्धारण करने की स्थिति से बहुत दूर है।

तेल एवं गैस अर्थव्यवस्था का एक और अहम पहलू यह है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं वस्तुओं से आता है। यही कारण है कि इन्हें अब तक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में नहीं लाया जा सका है। सरकार निगम कर और सरकारी स्वामित्व वाली तेल एवं गैस कंपनियों से लाभांश के जरिये भी राजस्व अर्जित करती है। सरकार के सामने तीन तरफा चुनौतियां हैं यानी घरेलू कीमतें नियंत्रित रखना, कर राजस्व में नुकसान से बचना और विदेशी मुद्रा व्यय एवं चालू खाता घाटा नियंत्रित करना। मौजूदा चुनौतीपूर्ण

हालात इस व्यवस्था के लिए एक गंभीर परीक्षा साबित होते हैं।

स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के नुकसान सहन करने की एक सीमा होती है। यह कोई नहीं जानता कि वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति कब तक बनी रहेगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ओएमसी सूचीबद्ध कंपनियां हैं जो सार्वजनिक शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह हैं।

जहां तक सरकार की बात है तो उसके पास यह बोझ उठाने के लिए राजकोषीय मोर्चे पर गुंजाइश बहुत कम है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रुपये को एक सीमा तक ही सहारा दे सकता है। मौजूदा प्रतिकूल हालात में रुपये में गिरावट थामना एक कठिन चुनौती है।

बाजार और उपभोक्ताओं को सही मूल्य निर्धारण का संकेत देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। महज बचत की अपील और आह्वान कारगर नहीं होंगे। इससे मुद्रास्फीति बढ़नी तय है, यह टाली नहीं जा सकती। कीमतों को अस्वाभाविक रूप से दबाए रखने से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। भविष्य में सरकार को लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंचे दाम से निपटने के लिए सिद्धांत-आधारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करनी चाहिए।

ऐसे हालात में केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपने कर राजस्व में कमी को स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसके उलट सामान्य से कम अंतरराष्ट्रीय कीमतें रहने पर केंद्र एवं राज्य कर दरें बढ़ा सकती हैं। उपयुक्त मकसद हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए आपसी तालमेल के साथ कदम उठाना अति आवश्यक है। निकट भविष्य में पेट्रोलियम को जीएसटी व्यवस्था के दायरे में लाना संभव नहीं है।

पारंपरिक उपचार पद्धति के संरक्षण में छत्तीसगढ़ बना मिसाल

वैद्यों ने किया ज्ञान और अनुभव साझा

■ 11 वैद्य सम्मेलनों से 1600 से अधिक वैद्यों को मिला प्रशिक्षण, हीलर हर्बल गार्डन और आधुनिक उपकरणों से बढ़ी क्षमता

रायपुर। वैद्य सम्मेलनों का आयोजन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और दुर्लभ जड़ी-बूटियों के ज्ञान को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक अत्यंत सशक्त माध्यम है। इन आयोजनों से अनुभवी वैद्यों के पास मौजूद स्थानीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण होता है और छात्रों व युवा चिकित्सकों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अनूठा अवसर मिलता है छ छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा राज्य की पारंपरिक उपचार पद्धतियों को संरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बोर्ड ने प्रदेशभर में 11 वैद्य सम्मेलनों का आयोजन कर पारंपरिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण पहल की है।

बोर्ड द्वारा आयोजित सम्मेलनों में एक राज्य स्तरीय, छह संभाग स्तरीय और चार जिला स्तरीय वैद्य सम्मेलन शामिल रहे। 8 अक्टूबर 2025 को आयोजित राज्य स्तरीय वैद्य सम्मेलन में लगभग 1100 वैद्यों ने भाग लिया, जबकि अन्य सम्मेलनों में करीब 1600 वैद्य शामिल हुए। इन आयोजनों में वैद्यों को औषधीय पौधों के वैज्ञानिक एवं वानस्पतिक नामों की जानकारी दी गई, जिससे उनके पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जा सके। साथ ही वैद्यों ने अपने अनुभवों और उपचार पद्धतियों का आदान-प्रदान भी किया।

सम्मेलनों में वैद्यों को औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए विनाश- विहीन विदोहन तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। इससे पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना उनका संग्रहण संभव हो सकेगा और भविष्य में भी इनका उपयोग जारी रहेगा।

बोर्ड द्वारा पिछले दो वर्षों से नवाचार योजना के तहत हीलर हर्बल गार्डन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से वैद्यों को उनकी बाड़ी में छोटे औषधीय उद्यान विकसित करने के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे आवश्यक वनौषधियां उनके घर के आसपास ही उपलब्ध हो रही हैं। बोर्ड द्वारा वैद्यों को उनके गांव के स्कूलों में स्कूल हर्बल गार्डन विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए तकनीकी मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों को औषधीय पौधों और स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वैद्यों को उच्च गुणवत्ता वाली औषधियां तैयार करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बोर्ड ने पिछले दो वर्षों में निःशुल्क पल्वराइजर मशीनें उपलब्ध कराई हैं। राज्य के 28 जिलों में कुल 40 मशीनें वैद्य समूहों को वितरित की गई हैं।

प्रत्येक मशीन का उपयोग 8 से 10 वैद्य सामूहिक रूप से कर रहे हैं। इससे जड़ी-बूटियों का बेहतर प्रसंस्करण संभव हो रहा है और उच्च गुणवत्ता वाली औषधियों के निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की ये पहलें न केवल पारंपरिक उपचार पद्धतियों को संरक्षित कर रही हैं, बल्कि वैद्यों को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इससे राज्य की समृद्ध स्वास्थ्य परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

47वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर सीएम साय ने दी विस अध्यक्ष सिंह को शुभकामनाएं

पीएम मोदी के नेतृत्व के 12 साल; मंत्री राजवाड़े ने की दीर्घायु होने की कामना

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के आज 12 साल पूरे हुए. इस अवसर पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने समता कॉलोनी स्थित खाटू श्याम मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की.मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश को आगे बढ़ा रहा है, उनकी दीर्घायु और निरंतर मार्गदर्शन की कामना करती हूं. भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को संवारने का काम कर रहा है, उनके नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ी है और विकास की गति तेज हुई है.

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम हो रहा है, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आई प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ नई ऊर्जा और नई सोच से देश का नेतृत्व कर रहे हैं.

वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के लोगों और पुरानी पीढ़ियों के घर-घर शौचालय की जरूरत को महसूस किया. महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए, कांग्रेस ने पहले प्रयास क्यों नहीं किए? भारत को राष्ट्र प्रथम बनाने की सोच विपक्षी दलों ने क्यों नहीं रखी? आज भारत आर्थिक दृष्टि से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, यह बड़ी उपलब्धि है सोच का फर्क होता है, हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार काम करता है.

महतारी वंदन योजना की किश्त को लेकर महिलाओं के परेशान होने पर लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि योजना की 28वीं किश्त हितग्राहियों के खातों में भेज दी गई है. नए नाम जोड़ने पर सरकार विचार कर रही है. ई-केवाईसी नहीं होने के कारण कुछ महिलाओं की राशि रुकी थी. 30 जून तक दस्तावेज अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं, जरूरत पड़ने पर समय सीमा बढ़ाई जा सकती है. जिनका भुगतान रुका है।

मोदी सरकार महिला सशक्तीकरण अन्त्योदय को समर्पित : रूपकुमारी

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों के कार्यकाल ने भारत में विकास की एक नई परिभाषा लिखी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा है कि यह कार्यकाल केवल बुनियादी ढाँचे के विकास का नहीं, बल्कि समाज के सबसे अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति और देश की 'मातृशक्ति' के व्यापक उत्थान का स्वर्णिम युग साबित हुआ है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद श्रीमती चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महिलाओं के जीवन को सुगम और गरिमापूर्ण बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 'उज्ज्वला योजना' के तहत करोड़ों गरीब माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति मिली, तो वहीं 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत बने शौचालयों ने महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित करना मोदी सरकार की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि है। श्रीमती चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन के जरिए हर घर नल से जल और जनधन खातों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार की हर योजना के मूल में नारी शक्ति का कल्याण छिपा है। रक्षा से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक, आज भारत की बेटियाँ हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। देश की जनता का यह अटूट विश्वास ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसके बल पर भारत आज 'विश्व बंधु' बनकर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।

रमेश कुमार शर्मा बने सहकारिता आयुक्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रमेश कुमार शर्मा को नई जिम्मेदारी सौंपी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने उनका ट्रांसफर करते हुए आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के पद पर पदस्थ किया है।

आपको बता दें वर्तमान में रमेश कुमार शर्मा गृह विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए नई पदस्थापना की है।

10 दिन खाली रहा पद

बताया जा रहा है कि बीते 10 दिन से ये पद खाली था। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद सरकार ने ये फैसला लेते हुए 2010 बैच के आईएएस अधिकारी रमेश कुमार शर्मा को आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के पद पर नियुक्त किया है। आदेश में ये भी कहा गया है कि यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। ये नियुक्ति राज्यपाल के नाम से जारी आदेश के माध्यम से की गई है। आपको बता दें ये आदेश डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ है। हालांकि इससे संकेत साफ हैं कि सरकार ने फिलहाल संविदा नियुक्ति के बजाय नियमित प्रशासनिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी है।

फिलहाल गृह विभाग के हैं सचिव

आपको बता दें रमेश शर्मा फिलहाल गृह विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। पर अब उन्हें सहकारिता विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी सरकार ने एक बार फिर अनुभवी और सक्रिय अधिकारियों पर भरोसा जताया है। गौरतलब है कि सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी ऐसे समय में दी गई है जब विभाग कई अहम योजनाओं और वित्तीय गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

मोदी के 12 साल झूठ की बुनियाद पर टिके रहे : बैज

रायपुर। मोदी के 12 साल झूठ की बुनियाद पर टिके रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी ने 12 सालों के कार्यकाल में 1 भी वादे को पूरा नहीं किया। मोदी ने 12 सालों के कार्यकाल में अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी और भाजपा देश की जनता से वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। विदेश से काला धन लाया जायेगा, हर के खाते में 15 लाख आयेंगे।35 रु. लीटर में डीजल, पेट्रोल देंगे हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करेंगे।2022 तक हर घर में नल। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करेंगे, कृषि उपजों का समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना किया जायेगा।100 स्मार्ट सिटी बनाया जायेगा।सभी सांसद एक गांव को गोद लेकर उसको आदर्श बनायेंगे। 2022 तक देश के हर आवासहीन का अपना मकान होगा। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। रुपया मजबूत होगा।मोदी जी को सरकार चलाते 12 साल पूरे हो गये लेकिन मोदी जी ने अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। मोदी के दोनों कार्यकाल कोरी बयानबाजी और लफ्फेदार भाषणों में निपट गया। अब भाजपा नेता मोदी के वादों पर बात करने से कतराते है।

राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल : शुक्ला

रायपुर। भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो गयी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह बेहद चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ में जिन मरीजों की मौते हो रही है। उनमें से 60 प्रतिशत से अधिक मरीजो की मौत केवल इसलिये हो रही है कि उनका समय पर ईलाज एक प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ से नहीं हो पाता है। सेंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ में होने वाली कुल मौतो के पीछे एक बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित डॉक्टरो की कमी है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ इस प्रकार की मौतो के मामलो में बिहार और झारखंड के बाद तीसरे स्थान पर है। भाजपा सरकार की प्राथमिकता में लोगो का ईलाज है ही नहीं, भाजपा सरकार के लिये स्वास्थ्य विभाग केवल भ्रष्टाचार करने का अड्डा मात्र बना हुआ है। प्रदेश के वर्तमान 10 मेडिकल कालेजो में 2660 स्वीकृत पदो में से 1290 पद लगभग आधे खाली पड़े है। ऐसे में मरीजो का कैसे ईलाज होगा। स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्रो में 65 प्रतिशत स्थानों तथा जिला अस्पतालो में 60 प्रतिशत पद खाली पड़े है। राज्य के सरकारी अस्पतालो में ईलाज कम भ्रष्टाचार अधिक होता है।

स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में भारी भ्रष्टाचार : ठाकुर

रायपुर। बिजली बिल में भारी भ्रष्टाचार और आम जनता को गुमराह कर लूटने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगाकर आम जनता को स्मार्ट तरीके से लूट रही है।बिजली उपभोक्ताओं को बीते माह की रीडिंग बिल दिया गया है उसकी भुगतान राशि मान लीजिये 910 रु है लेकिन उपभोक्ता बिल भुगतान करने जा रहा है तो 1700 रु के करीब बिल भुगतान लिया जा रहा है जो उपभोक्ता बिजली बिल भुगतान मोर बिजली ऐप से ऑनलाइन करते है उन्हें घर में पहुँची हुई रीडिंग बिल मान लीजिये 2880 रु मिला है लेकिन मोर बिजली एप में ऑनलाइन बिल पेमेंट की राशि 4440 रु भुगतान बकाया दिखाया जा रहा है। एक उपभोक्ता को 2980 रु का बिल दिया गया लेकिन जब भुगतान करने पहुँचा तो 4740 रु मांगा गया।जबकि रीडिंग बिल एवं मोर एप में बिजली खपत बराबर है बस राशि में हजारों रुपया का अंतर है ये तो सीधा-सीधा आम जनता को गुमराह कर लूटा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता पहले ही बिजली की महंगी दर,स्मार्ट मीटर के कारण अनाप शनाप बिजली बिल, लो वोल्टेज,बिजली कटौती से परेशान है।

धान का कटोरा और धान के किसान हमारी पहचान हैः वर्मा

रायपुर। धान के अलावा अन्य फसल लेने पर 15000 रू. प्रति क्विंटल देने के फैसले को भेदभाव पूर्ण और धान के किसान विरोधी बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, धान के किसान हमारी पहचान है, प्रदेश के अर्थव्यवस्था की धूरी है, भाजपा की सरकार दुर्भावना पूर्वक इसे मिटाने पर तुली है। आखिर इस सरकार को धान के किसानों से इतनी हिकारत क्यों? प्रदेश का जनवायु और मानसून धान के अनुकूल है। दलहन, तिलहन एवं अन्य फसल लेने के लिये न किसानों की तैयारी है, न ही वातावरण अनुकूल। सरकार पहले जो खाद का संकट सामने खड़ा है, उसका निराकरण करे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार का फैसला अव्यावहारिक है। धान के खेत में तिली, राहेर, कोदो, कुटकी, रागी, कपास, उड़द, मूंग कैसे बोयेंगे किसान? क्या किसान मेढ़ पार फोड़ कर, धान के खेत को पाट कर भर्री बना दे? छत्तीसगढ़ में मानसून, वर्षा, मिट्टी, जलवायु, धान के खेती के अनुकूल है, जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराने में नाकाम सरकार अपनी अक्षमता छुपाने अब 15 हजार का प्रलोभन दे रही है,

शिक्षा सत्र सामने शिक्षकों के पद खालीः वंदना कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपुत ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण सरकारी स्कूलों में आज भी शिक्षकों की भारी कमी है.भाजपा सरकार ने बड़े-बड़े विज्ञापन और घोषणाएं कर शिक्षकों की भर्ती का वादा तो किया, लेकिन आज तक भर्ती प्रक्रिया जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन 57000 हजार पद खाली पड़े हैं। सरकार की नीयत केवल प्रचार तक सीमित है, जबकि बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पूरी तरह उपेक्षित है। प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 5000 शिक्षकों के पद इसी शिक्षा सत्र में भरने की घोषणा किया था, वही भी नहीं भरे गये। भाजपा सरकार बताए, कि आखिर शिक्षकों की भर्ती की घोषणा केवल सुर्खियां बटोरने के लिए थी या वास्तव में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए? यदि सरकार गंभीर होती तो नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले नियुक्तियां पूरी हो चुकी होतीं।भाजपा सरकार में शिक्षकों की भर्ती की घोषणा के बावजूद अभी तक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियां क्यों नहीं हो पाई।

बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने की दिशा में होंगे नवाचारपूर्ण प्रयास

छत्तीसगढ़ विजन 2047 को मिलेगी गतिः मिश्रा

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ''अंजोर विजन-2047'' के माध्यम से छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल योजनाओं के निर्माण से नहीं, बल्कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय, सटीक आंकड़ों पर आधारित नीति निर्माण और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति से संभव होगा।

नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग में आयोजित स्टेट सपोर्ट मिशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट एवं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट्स के इंडक्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिश्रा ने कहा कि राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार ''अंजोर विजन-2047'' राज्य के दीर्घकालिक विकास का व्यापक रोडमैप है, जिसमें आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक प्रगति, निवेश संवर्धन और मानव विकास से जुड़े स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य और अंजोर विजन-2047 एक-दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों का मूल उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को इन लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्वित करना होगा। इस दिशा में राज्य नीति आयोग के अंतर्गत गठित एसएसएम, पीआईयू एवं एमएंडई इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अब राज्य का लक्ष्य केवल सूचकांकों में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाना है। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कृषि उत्पादकता, औद्योगिक विकास, महिला श्रम भागीदारी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य नीति आयोग के साथ कार्य कर रही विशेषज्ञ टीमों को विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर केपीआई आधारित समीक्षा, नीति विश्लेषण, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा साक्ष्य आधारित सुझावों के माध्यम से विकास की गति को और तेज करना होगा। उन्होंने अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से नवाचार, जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने का आह्वान किया।

अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, बिना अनुमति बन रहे 4 भवनों पर हुई कार्रवाई

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो प्रहरी अभियान के तहत जिला प्रशासन और नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम के जोन-5 क्षेत्र अंतर्गत चंगोराभाठा स्थित पवार भवन के पीछे बिना अनुमति बनाए जा रहे चार निर्माणाधीन भवनों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान श्रीडी मशीन की सहायता से भवनों में निर्मित दीवार, कॉलम, बीम, छज्जा एवं अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।

यह कार्रवाई रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार तथा नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई।नगर निगम जोन-5 के जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में कार्यपालन अभियंता लाल महेंद्र प्रताप सिंह, नगर निवेश विभाग के कार्यपालन अभियंता आशुतोष सिंह, सहायक अभियंता नागेश रामटेके एवं उप अभियंता टिकेंद्र चंद्राकर की उपस्थिति में कार्रवाई को अंजाम दिया गया।अनाधिकृत निर्माण हटाए गए।

नगर निगम, नगर निवेश विभाग, उड़नदस्ता दल तथा यातायात पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर चंगोराभाठा स्थित पवार भवन के पीछे निर्माणाधीन चार भवनों का निरीक्षण किया। जांच में निर्माण कार्य बिना अनुमति के पाया गया, जिसके बाद श्रीडी मशीन की सहायता से दीवार, कॉलम, बीम, छज्जा और अन्य निर्माण कार्यों को हटाया गया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.